



**BRIEF NEWS**

**एसपी ने किया औचक निरीक्षण, हवलदार निलंबित**  
**JAMTARA :** जामताड़ा जिले के एसपी राजकुमार मेहता मंगलवार की देर रात अचानक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने शहर के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने मंडल कारा जामताड़ा, व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, रात्रि गश्ती दल, टाइगर मोबाइल, पीसीआर एवं वन्युआरटी दल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में व्यवहार न्यायालय परिसर में तैनात हवलदार सिक्ंदर रवानी ड्यूटी से गावब पाए गए, जो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही मानी गई। अदालत जैसे संवेदनशील स्थल से अनुपस्थित रहना सुरक्षा दृष्टि से बड़ी चूक माना गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हवलदार सिक्ंदर रवानी को निलंबित कर दिया। इस दौरान मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की गई। एसपी ने निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।

**वॉलीबॉल के झगड़े में निकाला पिस्टल, दो गिरफ्तार**



**RAMGARH :** रामगढ़ जिला के पतरातू थाना क्षेत्र में वॉलीबॉल के खेल से शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो रहा था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से न सिर्फ झगड़ा खत्म हुआ, बल्कि पांडे गिरोह के शूटर इरफान उर्फ रेहान उर्फ छोटू सहित दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जानकारी बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पतरातू ब्लॉक परिसर में मंगलवार की शाम वॉलीबॉल का खेल चल रहा था। इस दौरान योगेश राम का बेटा विशाल राम और राजेश साव का भतीजा आकाश कुमार के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। बुलाया गया पांडे गिरोह का शूटरइस झगड़े के बाद आकाश के चाचा राजेश साव ने सीधे पांडे गिरोह से संपर्क किया। उसने आकाश की पिटाई का बदला लेने के लिए विशाल राम और उसकी मां को पीटा। इसके बाद उन लोगों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। मामले में जैसे ही पुलिस को इस खूनी संघर्ष की जानकारी मिली, पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। एसपी ने पतरातू पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीपीओ) गौरव गोरवामी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। योजना बनाते पकड़े गए अपराधीछापेमारी के दौरान सांकुल गांव में आम बगीचा पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान दो व्यक्ति पकड़े गए। इसमें पांडे गिरोह का शूटर पतरातू बस्ती दुर्गा मंडप निवासी इरफान उर्फ रेहान उर्फ छोटू और स्टेशन रोड निवासी राजेश साव उर्फ अर्यन शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर चार-पांच अपराधी फरार हो गए। इरफान के पास से 7.65 एएमएम लोडेड देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। एसपी ने बताया कि इरफान उर्फ रेहान उर्फ छोटू का अपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले भी बड़कागांव थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज हुई है। वर्ष 2021 में इसके खिलाफ बरकाकाना रेलवे थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पतरातू थाने में भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने बताया कि इरफान, पांडे गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

# चास में नवनिर्मित फोरलेन सड़क तीन फीट तक धंसी, बढ़ा हादसे का खतरा

## रोड के नीचे से गुजर रही नगर निगम की पाइपलाइन को बताया जा रहा कारण

● धर्मशाला मोड़ से पुरुलिया जाने वाली सड़क हुई क्षतिग्रस्त



इसी स्थान पर खतरा बढ़ रहा है

**PHOTON NEWS BOKARO :** बोकारो जिला स्थित चास में नवनिर्मित फोरलेन सड़क एक स्थान पर घंस गई है, जिसे स्थानीय लोग निर्माण में लापरवाही बता रहे हैं। धर्मशाला मोड़ से पुरुलिया जाने वाली इस सड़क पर वन विभाग के रेंजर ऑफिस के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा घंस गया है। बीच सड़क पर करीब तीन फीट गहरा गड्ढा बन गया है, जिसके चारों ओर दरारें फैल गई हैं। यह स्थिति इस व्यस्त मार्ग पर हादसे के बड़े खतरे को न्यौता दे

रही है। स्थानीय निवासियों ने तत्काल खतरे को देखते हुए टहनियां और लाल कपड़ा लगाकर रास्ता चिह्नित कर दिया है, ताकि रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों वाहन चालक सतर्क रहें।

**एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे दोनों विभाग**

सड़क घंसेने के कारणों को लेकर निर्माण कंपनी और पाइप एजेंसी एक-दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं, जबकि झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग मुकदशे का बना हुआ है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, सड़क घंसेने की वजह चास नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन है। विभाग के अभियंताओं का कहना है कि पाइप की टैरिस्टिंग के दौरान लीकेज हुआ, जिससे पानी रिसकर सड़क के नीचे की मिट्टी गीली हो गई और अंततः सड़क की ऊपरी परत टूटकर घंस गई। सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी अपनी गुणवत्ता को सही ठहरा रही है, जबकि पाइपलाइन टैरिस्टिंग करने वाली कंपनी लीकेज की जिम्मेदारी लेने से बच रही है।

**एजेंसी की अनदेखी से जनता में आक्रोश**

सबसे बड़ी लापरवाही पथ निर्माण विभाग की सामने आई है। विभाग का कार्यालय इसी क्षतिग्रस्त सड़क से महज 500 गज की दूरी पर स्थित है, इसके बावजूद विभाग के कार्यपालक अभियंता से लेकर अन्य कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझा। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही और टेकेदारों की मनमानी के कारण यह जानलेवा स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों ने मांग की है कि विभाग तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करे और लापरवाही के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके।

# बच्ची के गले में फंसा दो रुपये का सिक्का, डॉक्टर ने बचाई जान

AGENCY PALAMU :



एक्स-रे व पीड़ित बच्ची

जिले के हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में मंगलवार को एक आठ वर्षीय बच्ची की जान डॉक्टर की तत्परता और कुशलता से बच गई। हुसैनाबाद शहर के इस्लामगंज मोहल्ले के स्व. समीर आलम की पुत्री आठ वर्षीया पुत्री सबरीन प्रवीण खेलते समय गलती से दो रुपये का सिक्का निगल गई, जो उसके गले में फंस गया। बच्ची को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, तो परिजन आनन फानन में उसे लेकर अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचे। उस समय आपातकालीन ड्यूटी पर डॉ. विकास कुमार मौजूद थे। उन्होंने एक घंटे तक प्रयास किया, लेकिन सिक्का निकल नहीं पाया। इस बीच अनुमंडलीय अस्पताल में ही

**ऐसे निकला सिक्का**  
 डा. मंजूर ने बुधवार को सफलतापूर्वक सिक्का निकालने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई करते समय प्रशिक्षण के दौरान दो से तीन बार गले में फंसे सिक्के को निकाल चुके थे। इस कारण उन्हें इसका पुराना अनुभव था। बच्ची के गले में पाइप डालकर उसमें पानी भर दिया गया एवं उसे जोर जोर से खानसे के लिए बोला गया। दो मिनट तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला एवं सिक्का नर्मल पोजिशन से ही बाहर आ गया। डा. मंजूर ने कहा कि सिक्का अगर पांच का रहता तो अंदर चला जाता, लेकिन दो का सिक्का बड़ा था, इस कारण अटका रह गया। सिक्का के अंदर जाने पर शीव के रास्ते निकलने की संभावना रहती है, लेकिन तत्कालीन काफ़ी भी बढ़ जाती है।

मंजूर आलम की तत्परता और विशेषज्ञता के कारण ही उनकी बच्ची की जान बच सकी है।

# हजारीबाग पुलिस ने लूट की योजना बनाते चार हथियारबंद अपराधियों को किया गिरफ्तार

AGENCY HAZARIBAG :



पत्रकारों को मामले की जानकारी देते डीएसपी अमित आनंद

झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने लूट की योजना बनाते चार हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपितों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बरही के पुलिस उपाधीक्षक अमित आनंद ने बुधवार को बताया कि पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि चार हथियारबंद अपराधी दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरही की ओर लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही बरही देवचंदा मोड़ के पास पुलिस ने वानहों की जांच के लिए अभियान चलाया। जांच दल को देखकर अपराधी मोटरसाइकिल रोकने के बजाय भागने का प्रयास करने लगे,

लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस की पकड़ में आए अपराधियों की पहचान संतोष मुंडा (25) गुरुडीह, कटकमसांडी, हजारीबाग, दीनानाथ बेदिया उर्फ दिनेश बेदिया (34) डांड, कटकमसांडी, हजारीबाग, राहुल ठाकुर (27) सरीही, हजारीबाग और तुलेश्वर प्रजापति (31) डांड कटकमसांडी, हजारीबाग के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिल (जेएच 02 बीटी-

6811 एवं हीरो स्लेंडर जेएच 13एच-6072), एक देशी पिस्टल, एक देसी कट्टा, चार कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे पूर्व में हुई कई चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। छापेमारी दल में बरही के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल, बरही थाना के प्रभारी विनोद कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।



घर में बिखरे सामान

# सोने-चांदी के गहने और नकद 78 हजार की चोरी

HAZARIBAG :

सदर थाना क्षेत्र के कानी बाजार न्यू कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। पीड़ित आदित्य कुमार सिन्हा ड्यूटी पर गए थे, तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने और नकद 78 हजार रुपये और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए। घर लौटने पर टूटे-फूटे सामान और खाली कमरे को

देखकर परिवार सदमे में हैं। घटना के समय उनके परिवार के अन्य सदस्य शिवपुरी अपने नानी के घर गए हुए थे। पीड़ित ने सदर थाना हजारीबाग में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई कर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

# पलामू में विद्यालय से कंप्यूटर व उपकरणों की चोरी, दो गिरफ्तार

AGENCY PALAMU :



बरामद सामानों के साथ पुलिस गिरफ्त में आरोपी

जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र के उल्कमित उच्च विद्यालय बसना के आइसीटी लैब से कंप्यूटर उपकरण चोरी मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने कंप्यूटर उपकरण चुराने के लिए चोरी किए गए ऑटो कांड का भी खुलासा किया है। कंप्यूटर उपकरण को सरकारी शौचालय से बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी हैं। उनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। एसपी रिष्मा रमेश ने बुधवार प्रेस विज्ञापित जारी कर इसकी जानकारी दी। एसपी के अनुसार 13 अक्टूबर को रात बसना में गोविंद राम का ऑटो चोरी हो गया था। इसी रात उल्कमित उच्च विद्यालय बसना के लैब रूम से

कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण भी चोरी हो गई। संदिग्ध के अधार पर अमर कुमार राम बसना और दीपक पांडेय उर्फ छोटू पांडेय रजहाल को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि आयुष पांडेय उर्फ चांसी बसना और आयुष कुमार तिवारी तोलरा-रेहला के साथ मिलकर उल्कमित उच्च विद्यालय बसना के लैब रूम से कंप्यूटर

सहित अन्य उपकरणों की चोरी करने की योजना बनायी। 13 अक्टूबर की रात में सबसे पहले गोविंद राम-बसना के ऑटो की चोरी की। ऑटो लेकर स्कूल पहुंचे आरोपी और लैब रूम से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण चोरी करके उसी ऑटो से लौट गए और आयुष पांडेय उर्फ चांसी के घर के पास बने सरकारी शौचालय में छिपा दिया।

# घरोर पर्यटन विकास प्राधिकार की बैठक में पर्यटकों की सुविधाओं के सुदृढीकरण पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

## नेतरहाट टूरिज्म का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च

PHOTON NEWS LATEHAR:



वेबसाइट का प्रतिष्ठित दिखाते पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार व डीटी उल्कर्म गुप्ता

अरुणोदय गेस्ट हाउस, नेतरहाट में बुधवार को पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के सचिव सह अध्यक्ष नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार, मनोज कुमार की अध्यक्षता में नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में नेतरहाट को राज्य का प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, स्वच्छता, राजस्व, संचालन एवं आतिथ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को नेतरहाट पर्यटन को डिजिटल माध्यमों से और अधिक सशक्त एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में विजिट नेतरहाट आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च किया।

आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक पेज) <https://www.facebook.com/m/share/1EQMJxGreb/> आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (Instagram) <https://www.instagram.com/>

[m/visitnetarhat/igsh-MWRKZHK1dnZM2kwZw](https://www.instagram.com/m/visitnetarhat/igsh-MWRKZHK1dnZM2kwZw) आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (Twitter) <https://x.com/visitnetarhat?t=JLfrGY.JqlBTDOfrkAZDUkw@s-09>

**सौंदर्यीकरण व सुविधाओं पर दिए गए निर्देश**

बैठक में निम्नांकित प्रमुख बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया झहेलीपेड से जंगल वारफेयर स्कूल तक सड़क मरम्मत एवं चौड़ीकरण करने, दुर्गा मंदिर से सनसेट पॉइंट एवं बडुआ टोली तक की तक सड़क मरम्मत कार्य, बडुआ टोली में पार्किंग सुविधा के लिए सड़क सिगल होने से जुड़ा निर्णय, कोयल वू पॉइंट एवं अन्य पर्यटन स्थलों के पास पार्किंग की व्यवस्था, पठार बाजार एटीएम (एसबीआई) के बगल में दायीं ओर पार्किंग की व्यवस्था, नेतरहाट पर्यटन प्राधिकरण कार्यालय एवं सभागार कक्ष का सौंदर्यीकरण, संग्रहालय (यूजियम) का अधिष्ठापन, नेतरहाट में मार्केट कॉम्पलेक्स का विकास, जैव विविधता पार्क एवं तितली पार्क का निर्माण, पर्यटन स्थलों पर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन, भवन निर्माण का नियमितीकरण, अवल अधिकारी, महुआडांड पंचायत नेतरहाट के लिए एक लैंड बैंक तैयार करना, पर्यटन सीजन के दौरान होमगार्ड की अतिरिक्त तैनाती, पर्यटन स्थलों पर पुलिस पोस्ट की आवश्यकता पर चर्चा, सड़क सुरक्षा के लिए सीसीटीवी व एएनपीआर कैमरा लगाने, शराब पीकर वाहन चलाने पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया।

प्रबंध निदेशक, नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार, उल्कर्म गुप्ता, उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमंडल कुमार आशीष, उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल ब्रजेश कान्त जेना, उपविकास आयुक्त, लातेहार सैय्यद रियाज अहमद, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार, अजय कुमार राजक, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड बिपिन कुमार दुबे, डीआरडीए निदेशक प्रभात रंजन चौधरी, गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी श्रेयाश, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, जिला खेल सह पर्यटन पदाधिकारी अविनेश कुमार त्रिपाठी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआडांड, अंचल अधिकारी, महुआडांड, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, पर्यटन प्राधिकरण के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

**प्लास्टिक मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता**

प्लास्टिक मुक्त नेतरहाट अभियान के जुमाने पर फैसला, नेतरहाट में सीजीएलएम की शुरुआत करना, शुल्क निर्धारण एवं जुमाने का प्रावधान, नेतरहाट महोत्सव एवं नक्षत्र महोत्सव के आयोजन पर चर्चा, लिकर लाइसेंस से संबंधित, लिकर लाइसेंस एवं कोयल वू पॉइंट का संचालन, पर्यटन गाइडों के लिए नामांकन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करने, होटल, लॉज, होम स्टै, टैट आदि का पंजीकरण एवं सीसीटीवी अनिवार्यता, नेतरहाट के होटलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण, सभी दूर ऑपरेटर्स को पंजीकरण एवं अनुमति, सोशल मीडिया हैंडल संचालन एवं नेतरहाट में प्रवेश शुल्क निर्धारण, नेतरहाट स्कूल की भूमि संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नेतरहाट में पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

**रामगढ़ में बिजली चोरी के आरोप में 10 लोगों पर जुर्माना व प्राथमिकी**

**RAMGARH :** रामगढ़ में बिजली चोरी के आरोप में सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार सिंह ने थाना में 10 लोगों पर जुमाने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को दिए आवेदन में अभियंता की ओर से बताया गया है कि 14 अक्टूबर को बिजली चोरी रोकथाम के लिए एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। छापेमारी के दौरान अवेध रूप से बिजली का उपयोग करते 10 लोग पाए गए। बिजली विभाग की ओर से कोठार निवासी अजय कुमार जायसवाल पर 30 हजार, रज्जि प्रसाद जायसवाल पर 30 हजार, धीरेन जायसवाल पर 25 हजार, ऊपर टोला कोठार निवासी अजीत कर्माणी पर 10 हजार 500, दिलेश्वर मुंडा पर 10 हजार 500, बेटर निवासी सुनील मुंडा पर 5 हजार 500, गोसा निवासी एकनाथ महतो पर 15 हजार 500, तोषेवर महतो पर 15 हजार 500, दिलीप महतो पर 25 हजार 500 और शहजाद अहमद उर्फ शहजाद खान पर 5 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया है। सहायक अभियंता की शािकायत पर पुलिस ने उपरोक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है।

**BRIEF NEWS**

**रांची के कई इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली**

**RANCHI :** राजधानी रांची में गुरुवार को पावर सब स्टेशन पॉलीटेक्निक में मीटरिंग यूनिट लगाने से संबंधित कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत शक्ति उपकेंद्र पॉलीटेक्निक से निकलने वाले 11 केवी के सभी फीडर की विद्युत आपूर्ति अलग-अलग समय में डेढ़ घंटे के लिए बाधित रहेगी। यह जानकारी बुधवार को बिजली विभाग की ओर से दी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रांची के जिन इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी, उनमें 11 केवी मेन रोड में सुबह आठ बजे से 9.30 बजे तक, 11 केवी बासटोली में सुबह 9.30 बजे से 11.00 बजे तक, 11 केवी सुजाता में सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक, 11 केवी चर्च रोड में दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2:00 तक और 11 केवी पथलकुदवा में दोपहर दो बजे से दोपहर 3.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

**शिव शक्ति हनुमान मंदिर काली पूजा समिति ने किया भूमि पूजन**

**RANCHI :** शिव नगर कमांडे स्थित शिव शक्ति हनुमान मंदिर काली पूजा समिति की ओर से मां काली पूजा को लेकर भूमि पूजन का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। समिति के सदस्यों ने विधिवत मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर मां काली से समृद्धि और मंगल की कामना की। समिति ने बताया कि इस वर्ष मां काली की पूजा भव्य और आकर्षक रूप में आयोजित की जाएगी। 20 अक्टूबर को शाम 7 बजे पंडाल उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जिसके बाद रात्रि में मां काली की पूजा संपन्न की जाएगी। अगले दिन 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से माता का महाभोग आयोजित होगा। इसके बाद शाम 5 बजे से माता का चैता और रात्रि 7 बजे से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय डांस ग्रुप अपनी शानदार प्रस्तुति देंगी। पूजा समिति के पदाधिकारियों में अध्यक्ष सनी वर्मा, उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, कोषाध्यक्ष राज चौधरी शामिल हैं।

**पीसीसी सड़क निर्माण का हुआ शिलान्यास**

**RANCHI :** तमाड़ प्रखण्ड के नुरीडीह में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा की निधि से बनने वाली 550 फीट पीसीसी सड़क का विधिवत शिलान्यास किया गया। नारियल फोंड्रकर उद्घाटन ग्राम प्रधान सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मुंडा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गोलक दास अधिकारी, पूर्व जिला सदस्य अनुरु साहू, मुखिया अनिता देवी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा और डॉ. प्रदीप वर्मा के समर्थन में नारे लगाए। सड़क निर्माण से गांव में आवागमन सुगम होने की उम्मीद से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया।

**बीआईटी मेसरा के 16 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से किया गया सम्मानित**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

बुधवार को बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) मेसरा में भव्यता और उत्साह के साथ 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 1400 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां और मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. वी नारायणन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में 1000 स्नातक, 320 स्नातकोत्तर, 75 पीएचडी और 65 डिप्लोमा विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 16 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डॉ. वी नारायणन ने अपने संबोधन में छात्रों को विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने, सतत

- अतिथियों ने 1400 से अधिक स्टूडेंट्स को प्रदान की डिग्रियां और मेडल
- डॉ. वी. नारायणन ने विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने और हमेशा सीखने पर दिया जोर
- जीवन के हर चरण में संवेदना, सहयोग और उद्देश्य की भावना का समझाया महत्व

**35वें दीक्षांत समारोह में इसरो प्रमुख की मौजूदगी से नई पीढ़ी को मिली प्रेरणा**



दीक्षांत समारोह में भाग लेते इसरो अध्यक्ष डॉ. वी नारायणन व अन्य

**नवाचार के लिए आजीवन खोज की शुरुआत**

बीआईटी मेसरा के कुलाधिपति और सीके बिरला समूह के अध्यक्ष सीके बिरला ने कहा कि दीक्षांत केवल एक शैक्षणिक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जिज्ञासा और नवाचार की आजीवन खोज की शुरुआत है। आज दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो स्पष्ट सोच, ईमानदारी से कार्य करें और उद्देश्यपूर्ण निर्माण करें। मुझे विश्वास है कि बीआईटी मेसरा के विद्यार्थी इस परिवर्तन की अगुवाई करेंगे।

**कुलपति ने प्रस्तुत किया वार्षिक प्रतिवेदन**

कुलपति प्रोफेसर इंद्रीला मन्ना ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्थान की शोभा, नवाचार और वैश्विक सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा में हम शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि दृष्टि, सार्वजनिक और नेतृत्व क्षमता के विकास का साधन मानते हैं। हमारे विद्यार्थी भविष्य में उद्योग, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। समारोह के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और मंच संचालन टीम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। समारोह संचालक ने संकाय, कर्मचारियों और दीक्षांत समारोह समिति के योगदान को स्वीकार करते हुए हार्दिक धन्यवाद दिया।

**स्वतः संज्ञान पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा-**

**तीन बस स्टैंडों का कार्यापलट होने में कितना लगेगा समय**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

राजधानी रांची के आईटीआई बस स्टैंड और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, कांटाटोली की बदहाल स्थिति मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि आईटीआई बस स्टैंड, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, कांटाटोली और रांची रेलवे स्टेशन रोड स्थित सरकारी बस डिपो का आधुनिकीकरण किया जाना है। इन तीनों बस स्टैंड का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कर मॉडर्न बस स्टैंड बन जाना है। इसके लिए 47172 करोड़ रूपया खर्च होंगे। इस योजना को सरकार ने मंजूरी दी है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इन्हें कब तक बेहतर बनाया जाएगा और क्या-क्या चीज बनाए जाएंगी इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं फरवरी 2024 में आईटीआई बस स्टैंड, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, कांटाटोली को दुरुस्त करने को लेकर निकाले गए टेंडर पर क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने इस पर

**रातू रोड प्लाईओवर के नीचे खड़े ऑटो से बढ़ रहे जाम से जल्द मुक्ति दिलाए प्रशासन**



रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पक्ष रखा। सरकार की उसे अधिवक्ता पियूष चित्रसे ने पक्ष रखा। कोर्ट ने

रातू रोड प्लाईओवर के नीचे नागा बाबा खटाल के पास जहां-तहां टोपों के लगे रहने से जाम की समस्या पर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम से कहा कि रातू रोड प्लाईओवर के नीचे टोपों के लगे रहने से होने वाले जाम से जल्द लोगों को मुक्ति दिलाए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी एवं रांची नगर निगम की एक बैठक हुई थी। जिसमें दो जगहों नागा बाबा खटाल के वेजिटेबल मार्केट के बेसमेंट और जाकिर हुसैन पार्क के पुराने स्टैंड को पार्किंग स्थल के रूप में बनाने का सुझाव आया था। जिस पर ट्रैफिक डीएसपी ने इन दोनों स्थानों का भौतिक सत्यापन किया। पाया कि इन दोनों जगह पर पार्किंग स्थल बनाने में कई समस्याएं हैं। नागा बाबा खटाल के वेजिटेबल मार्केट के बेसमेंट में दीवारों से पानी रिसता है, लाइट की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं जाकिर हुसैन पार्क स्थल पर जमीन समतल नहीं है, लाइट की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां कुछ गड्ढा में पानी का जमाव है। ट्रैफिक डीएसपी ने इन दोनों स्थलों को दुरुस्त करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। खंडपीठ ने मामले में रांची नगर निगम और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले के अगली सुनवाई 13 नवंबर निर्धारित की है।

कोर्ट ने गंभीरता से लिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इसपर स्वतः संज्ञान लेते हुए पीआइएल में बदला है।

**काली पूजा को लेकर एक्टिव हो गई रांची नगर निगम की टीम**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के बाद अब रांची में काली पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासक सुशांत गौवर्धन के निर्देश पर रांची नगर निगम की टीम शहर भर में सफाई और अन्य जरूरी काम कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। नगर निगम की टीम शहर की लगभग 70 काली पूजा समितियों से लगातार संपर्क में है। समितियों के माशेली न होने और सुझाव लेकर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को निगम की टीम ने कांसमोस यूथ क्लब, श्री श्री काली पूजा समिति, तूफान क्लब, अग्रदूत क्लब, कर्कट रोड समिति, अमर ज्योति समिति, डोरंडा समिति समेत कई आयोजकों से मुलाकात कर सहयोग दिया। पूजा



पंडालों और आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कूड़े का उठाव, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव, घास की कटाई, नालियों की सफाई का काम जारी है?। स्टोन डस्ट और जेएसबी मशीने से पंडालों तक जाने वाले रास्तों को समतल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की खराबियों को ठीक किया जा रहा है। सभी टॉयलेट और सुलभ शौचालयों की सफाई की जा रही है। एम्फोसमेंट टीम द्वारा सड़कों पर खड़े ट्रक, ठेले और अवैध पार्किंग हटाई जा रही है, ताकि आवागमन आसान रहे।

**ओरंडा में स्वामी नारायण मंदिर की थीम पर बनाया जा रहा काली पूजा पंडाल**

**RANCHI :**

झारखंड की राजधानी रांची में काली पूजा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शहर के अलग-अलग स्थानों पर पंडाल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति इस वर्ष स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य काली पूजा का आयोजन कर रही है। समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बुधवार को बताया कि इस वर्ष का पंडाल अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर की थीम पर तैयार किया जा रहा है। पंडाल की ऊंचाई 90 फीट और चौड़ाई 100 फीट होगी। इसके निर्माण में बंगाल से आए लगभग 250 कारीगर जुटे हुए हैं। कारीगर तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं। पूजा और पंडाल निर्माण में लगभग 50 लाख रुपये लगेंगे।

**स्वदेशी उत्पादों से आत्मनिर्भर भारत का पूरा होगा संकल्प : दुल्लू महतो**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

बुधवार को भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के रातू रोड स्थित कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित रांची विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जिला अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में हुआ। धनबाद के सांसद दुल्लू महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए और चले गए। सबसे स्वदेशी की बात अपने कार्यकाल के दौरान की, लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्पों द्वारा ही पहली बार स्वदेशी अपनाता और स्वदेशी को घर-घर तक पहुंचाने में सफलता मिली। इस अभियान में अब हमें भी अपनी भागीदारी देनी



आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में सांसद दुल्लू महतो व अन्य

ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना तथा भारतीय भाषण भाषाओं का उपयोग करने के लिए अलख जागना होगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि अपने आसपास में किसी भी तरह के

**एचडीसी मजदूरों को भड़काने में लगे हैं कुछ नेता : भवन सिंह**

**RANCHI :**

हटिया मजदूर यूनियन के तत्वावधान में बुधवार को एफ-एफपी बिल्डिंग शेड में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में स्थायी और सप्लाई मजदूर शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने की और संचालन महामंत्री हरिश्चंद्र रजवार ने किया। बैठक में भवन सिंह ने कहा कि सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति न तो निर्बंधित संस्था है और न ही मान्यता प्राप्त संगठन है। इनके नेता मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय मजदूरों को भड़काने में लगे हैं। यदि वे वास्तव में मजदूरों का भला चाहते, तो झारखंड में डीए लागू कराने, एएल छुट्टी और बोनस दिलाने जैसी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने की पहल करते।

**दीपोत्सव**

पिछले साल की तुलना में 20% तक बढ़ी कीमतें, ग्रीन क्रैकर्स की डिमांड में इजाफा

**राजधानी के विभिन्न इलाकों में सज चुका पटाखों का बाजार**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

दीपोत्सव रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ-साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक पटाखों की रौनक दिखाने दे रही है। मोरहाबादी मैदान में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी विशेष पटाखा बाजार सजाया गया है। सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय गैर-सहजताओं का पालन करते हुए यहां पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। फायर सेफ्टी, बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बाजार में कई बड़े ब्रांड के ग्रीन और इको-



फ्रेंडली पटाखे उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों से ग्रीन पटाखों का चलन बढ़ा है। इस वर्ष भी ग्राहकों की पहली पसंद यही बन रहे हैं। विक्रेताओं के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार पटाखों की कीमतों में 15 से

**पर्यावरण और सुरक्षा दोनों पर फोकस**

कंपनियों ने इस साल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम धुआं और कम आवाज वाले पटाखे बनाए हैं। ये ग्रीन श्रेणी में आते हैं और वातावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी बाजार में सुरक्षित और रंगीन पटाखों की विशेष रेंज उपलब्ध है। विक्रेताओं का कहना है कि बच्चों के लिए ऐसे पटाखे तैयार किए गए हैं, जिनसे किसी भी प्रकार की चोट या प्रदूषण की संभावना बेहद कम है।

**पर्व नजदीक आने के साथ बढ़ेगी ग्राहकों की संख्या**

फिलहाल पटाखा बाजार में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली नजदीक आने के साथ ही ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। मोरहाबादी का यह पटाखा बाजार इन दिनों रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक पैकेजिंग से दमक रहा है। पटाखों के शौकीनों के लिए यहां हर तरह की वैरायटी मौजूद है। पारंपरिक फुलझड़ी से लेकर नए डिजाइन वाले इको-फ्रेंडली क्रैकर्स तक। दीपावली की तैयारी के बीच राजधानी रांची का पटाखा बाजार इस समय पूरी तरह सज-धज कर त्योहार का स्वागत करने को तैयार है।

**हमर अधिकार मंच (हम) का हुआ गठन दीपेश बने अध्यक्ष**

**RANCHI :**

रांची में बुधवार को आम लोगों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में विस्तृत अधिकारों पर जागरूकता और उनके क्रिया-व्ययन एवं आम लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा देने के उद्देश्यसे हमर अधिकार मंच (हम) का गठन किया गया। हमर अधिकार मंच के गठन और पंजीकरण की प्रक्रिया भीम जिला अवर निबंधक कार्यालय में संपन्न हुई। हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने बताया कि हमर अधिकार मंच का गठन का मुख्य उद्देश्य नागरिक अधिकारों पर चर्चा, संवाद और जागरूकता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संचालन के भाग-3 हमें मौलिक अधिकार देता है और मानव अधिकार के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है।

**विकास ग्राम सेवा संस्थान ने 101 कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह**



**PHOTON NEWS RANCHI :**

से गरीब कन्याओं का चयन कर संस्था ने निःशुल्क विवाह संपन्न करवाया। सभी का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह में अन्य धर्म के लोग भी शामिल थे। कुछ जोड़े ईसाई धर्म के होने के बावजूद हिंदू रीति-रिवाज से सभी हिंदू कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह का उद्घाटन संस्था के महावीर खलको ने किया तथा संचालन संस्था के सचिव विकास भूषण ने। विकास भूषण ने बताया कि झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, घाघरा, खूंटी और रामगढ़

## समाचार सार

## नक्सलियों ने मोबाइल टावर को लगाई आग

**CHAIBASA :** पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर मोबाइल टावर को निशाना बनाया है। बुधवार को दिन में छोटानागरा थाना क्षेत्र के कुदलीबाद में नक्सलियों ने मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। सूचना के अनुसार, बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे दर्जनों नक्सलियों का जत्था गांव पहुंचा। नक्सलियों ने गांव वालों को अपने-अपने घर के अंदर जाने को कहा और टावर को आग के हवाले कर दिया। इसमें टावर के समीप स्थित विद्युत संयंत्र जलकर खाक हो गया। नक्सलियों ने ग्रामीणों को जंगल जाने से मना करते हुए, घटना को लेकर पुलिस की मुखबिरी नहीं करने की चेतावनी भी दी। मामले को लेकर पुलिस द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह घटना बीते शनिवार को जराइकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा में एयरटेल मोबाइल टावर और सोमवार को छोटानागरा थाना क्षेत्र के बहदा गांव स्थित एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले करने के बाद हुई है। लगातार मोबाइल टावरों को निशाना बनाने से सारंडा क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था चरमरा गई है और लोग दूरसंचार व्यवस्था से कटते जा रहे हैं।

## नक्सली बंद का मिला-जुला रहा असर

**CHAIBASA :** भाकपा-माओवादी नक्सली संगठन द्वारा बुधवार को आहत बंद का मिला-जुला असर दिखा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा और चक्रधरपुर के शहरी क्षेत्र को छोड़कर आसपास के गांवों-कस्बों में बाजार की तमाम दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। जिले के किराबुर, जमनाथपुर, मझगांव, बंदगांव, सोनुवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर, आनंदपुर आदि कई प्रखंडों में बैंक की शाखाओं, पेट्रोल पंप, डाकघर में ताले लटकते रहे। चाईबासा और चक्रधरपुर में आम दिनों की तरह बाजार खुले थे। लेकिन, जिले के अन्य हिस्सों में सन्नाटा पसर रहा। चाईबासा से रांची जाने वाली यात्री बसें नहीं चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों के पहिए थमते ही सड़कों पर सन्नाटे की स्थिति रही। बता दें कि भाकपा-माओवादी नक्सलियों ने पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाते और 15 अक्टूबर को बंद का एलान किया था। नक्सलियों के इस बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमों जिले के विभिन्न हिस्सों में गश्त कर रही थीं।

**महिला विवि का तीसरा दीक्षांत समारोह नवंबर में**  
**JAMSHEDPUR :** जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय (जेडब्ल्यूयू) का तीसरा दीक्षांत समारोह नवंबर में होने जा रहा है। यह समारोह सत्र 2024-25 के सभी स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों और चर्चनित स्नातक (यूजी) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्राओं के लिए होगा। समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें डिग्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक छात्राएं 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन शुल्क मात्र 1000 रुपये प्रति छात्रा है। आवेदन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.jwu.ac.in](http://www.jwu.ac.in) के माध्यम से किया जा सकता है। सफल आवेदन पर डिग्री प्रमाणपत्र समारोह में वितरित किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने छात्राओं को सलाह दी है कि वे समय रहते दस्तावेज अपलोड करें—जैसे मार्कशीट, फोटो और आईडी प्रूफ। हेल्लोलाइन नंबर पर सहायता उपलब्ध है। अब तक सैकड़ों छात्राओं ने आवेदन जमा कर दिया है।

## भिलाई पहाड़ी के पास मुखिया प्रतिनिधि पर हमला

**JAMSHEDPUR :** नेशनल हाईवे-33 पर बुधवार को वाहनों को आगे-पीछे करने में दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया। इसी बीच मानगो के रहने वाले राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिस्टल निकाल कर पलासबनी के मुखिया प्रतिनिधि सुफल सिंह पर हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर एमजीएम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में सुफल सिंह के आवेदन पर पुलिस ने प्रारंभिकी दर्ज कर ली है। राजा सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताते हैं कि सुफल सिंह घाटशिला की तरफ से जमशेदपुर आ रहे थे। जबकि, राजा जमशेदपुर से घाटशिला की तरफ जा रहे थे। सुफल सिंह अपनी बोलोरो कार में थे, जबकि राजा सिंह क्रेटा कार में। इसी दौरान भिलाई पहाड़ी के पास दोनों लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और वहीं गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर उनमें बहस हो गई। सुफल सिंह का आरोप है कि इसी बीच राजा सिंह ने पिस्टल निकाल ली और इसके बट से हमला कर दिया।

## युवक की फंदे पर लटकी मिली लाश

**CHAIBASA :** पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के मुफरिसल थाना अंतर्गत करलाजोडी गांव में एक 25 वर्षीय आदिवासी युवक की फंदे पर लटकी हुई लाश मिली। मृतक साधु चरण पुरती के परिवार में बताया कि वह नशे का आदी था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। वह कुछ दिनों से अधिक मात्रा में नशे का सेवन कर रहा था। मना करने पर भी नहीं छोड़ रहा था। मंगलवार को भी वह शाम को नशे में धुत होकर घर आया और अपने कमरे में चला गया। जब परिवार में उसे खाना खाने के लिए आवाज लगाई, तो वह कमरे से नहीं निकला। बाद में खिड़की से देखा गया तो वह फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया।

**मुजताबा रिज्वी @ JSR :** घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। चुनाव के दौरान अगर किसी सियासी दल को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सभा करनी होगी तो इसके लिए उनके स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर कहां उतराया, इसका भी प्रबंध जिला प्रशासन ने कर लिया है। सियासी दलों की सूचना पर भवन निर्माण हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाएगा। दो तरह के हेलीपैड बनाए जाएंगे। हेलीपैड के इस्तेमाल के बदले में सियासी दल को शुल्क देना होगा। जिला प्रशासन ने शुल्क चार्ज बुधवार को जारी कर दिया है। भवन निर्माण दो तरह के हेलीपैड बनाएगा। एक ऐसा हेलीपैड होगा, जिसमें बैरिकेडिंग के साथ ही सारी

6200 रुपये प्रति छह घंटा के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। बिना बैरिकेडिंग वाले हेलीपैड के लिए कुल 15 हजार 242 रुपये लिए जाएंगे। इसमें हेलीपैड का 7542 रुपये शुल्क है। एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये और अग्निशमन दल के लिए प्रति छह घंटे 6200 रुपये का शुल्क इसमें शामिल है। अगर किसी सभा में छह घंटे से अधिक का समय लग रहा है तो अग्निशमन दल का शुल्क अलग से लिया जाएगा। अगर कोई सियासी दल किसी निजी जमीन पर हेलीपैड बनवाना चाहता है तो उसे जमीन के मालिक से एनओसी लेनी होगी। जमीन का क्रियाय सियासी दल ही भुगतान करेगा। सरकारी जमीन पर हेलीपैड बनाने से पहले सियासी दल को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

## हथियारबंद अपराधियों ने लूटे ढाई लाख रुपये, सोने की चेन व ब्रेसलेट

## परिवार को बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने शुरु की जांच-पड़ताल

## PHOTON NEWS CHAIBASA :

पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ाजामवा में सोमवार की आधी रात को लूट की घटना हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। फुटबॉल मैदान स्थित अनिल चौरसिया के घर पर पांच हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर परिवार को बंधक बनाया और घर में रखे करीब ढाई लाख रुपये नकद, एक सोने की चेन और सोने की ब्रेसलेट लूटकर फरार हो गए।

परिजनों ने बताया कि रात करीब 12 बजे के बाद पांचों अपराधी अनिल चौरसिया के घर में पीछे के रास्ते से घुसे। परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही अपराधियों ने हथियार तानकर सभी को बंधक बना लिया।



करीब 15 मिनट तक चले इस पूरे घटनाक्रम में अपराधियों ने घर के कोने-कोने की तलाशी ली और जो कुछ भी हाथ लगा, समेट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार को पीड़ित अनिल चौरसिया ने बड़ाजामवा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी बालेश्वर

उरांव के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घर का निरीक्षण किया।

डीएसपी ने बताया कि घटना बेहद संगठित तरीके से अंजाम दी गई है। पुलिस ने संदिग्ध इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है और अपराधियों के भागने की संभावित दिशा में चेकिंग भी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। घटना के समय आसपास के क्षेत्र में एक सफेद रंग की बाइक और एक स्कूटी के देखे जाने की सूचना मिली है। पुलिस इस कोण से भी जांच कर रही है कि क्या अपराधियों ने पहले से इलाके की रेकी की थी।

## PHOTON NEWS SERAIKELA :

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में अपराधियों ने बुधवार को दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे डाला। अपराधियों ने राजनगर थाना क्षेत्र के छोटा सिजुलता स्थित नवोदय चौक के पास स्थित एक फोटो स्टूडियो सह ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) में लूट की और फायरिंग करते हो फरार हो गए। पुलिस ने अनुसार, आज तीन युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचे और हथियार के बल पर संचालक अनूप महाकुड़ से 60 हजार रुपये नकद लूट लिए।



घटनास्थल पर जांच करते पुलिस अधिकारी

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाते हुए अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। इसी दौरान अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, लेकिन भीड़ को पास आता देख उन्होंने तीन राउंड फायरिंग की। हालांकि, इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खानबीन शुरू कर दी है।

## ट्रॉंसमिशन टावर को लेकर अपने वादे पर खरा नहीं उतरा बिजली विभाग, दो दिन अंधेरे में रहा मानगो

## बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोग हो गए परेशान, उमस व मच्छर के चलते रात भर नहीं आई नींद

## PHOTON NEWS JSR :

मानगो में नेशनल हाईवे-33 पर ट्रॉंसमिशन टावर बनाया जा रहा है। इसके चलते मानगो में दो दिन से बिजली आपूर्ति ठप है। यह ट्रॉंसमिशन टावर मंगलवार की शाम को ही बन कर तैयार हो जाना था, मगर बुधवार की रात तक काम पूरा नहीं हो पाया है। बिजली विभाग ने जनता से कहा था कि रोडेशन के आधार पर हर इलाके में बिजली आपूर्ति की जाएगी। मगर, यह रोडेशन मजाक बन कर रह गया है। मानगो के जवाहर नगर, पारडीह, डिमना, आजाद बस्ती और इलाकों में दो-तीन घंटे बाद 15 मिनट के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दो दिन से मानगो



में बिजली आपूर्ति की जो हालत रही, उससे लोग परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने कहा था कि ट्रॉंसमिशन टावर का निर्माण मंगलवार की शाम छह बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वह जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं देता चाहते। लेकिन, बिजली विभाग का यह वादा पूरा नहीं उतर पाया है। विभाग यह काम मंगलवार को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि बुधवार को दोपहर बाद दो बजे तक हर हाल में काम

कर लिया जाएगा। तब तक मानगो, पटमडा और बोड़ाम इलाके में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। थोड़ी देर के लिए रोडेशन के आधार पर बिजली दी जाएगी मगर, विभाग ट्रॉंसमिशन टावर का निर्माण मंगलवार को पूरा नहीं कर पाया है। जेबीवीएनएल के जीएम ने भरोसा दिलाया था कि मंगलवार की शाम छह बजे तक हर हाल में काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वह जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं देता चाहते। लेकिन, बिजली विभाग का यह वादा पूरा नहीं उतर पाया है। विभाग यह काम मंगलवार को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि बुधवार को दोपहर बाद दो बजे तक हर हाल में काम

पूरा कर बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। मगर, बुधवार की शाम चार बजे तक भी काम पूरा नहीं हो पाया था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तो जीएम को भी गलत सूचना दे दी थी। उन्हें बताया गया था कि मानगो के डिमना रोड के इलाकों को छोड़ कर बाकी हर जगह बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मगर, ऐसा नहीं था। जवाहर नगर रोड नंबर 15, समेत कई इलाके फिर भी अंधेरे में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। डिमना रोड के रहने वाले राजेश कुमार कहते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारियों पर कैसे भरोसा किया जाए। यह कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ।

## झाटीझरना गांव की सड़क की बदहाली से ग्रामीण परेशान

## GHATSILA :

पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र झाटीझरना पंचायत के झाटीझरना गांव में मुखिया के घर के समीप वाली सड़क लगभग 200 मीटर लंबी है। वह भी 6 महीने से अधूरी है। इस पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो गया है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस सड़क पर साइकिल व बाइक के पलट जाने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब भी ठेकेदार या मुंशी से बात की जाती है तो स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। ठेकेदार ने उक्रेमिंत उच्च विद्यालय झाटीझरना के उर्दू शिक्षक डॉ. कमर अली को बताया कि हमारी बड़ी गाड़ी यहां तक नहीं आ पाएगी और छोटी गाड़ी से सामान लाने में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हमलोगों ने



सड़क के गुजरता बाइक सवार

इसे अधूरा छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस सड़क को जल्द से जल्द किसी भी हाल में पूरा करा दें, वरना आंदोलन छिड़ जाएगा। देखने वाली बात यह है कि यह चुनाव का समय है। ऐसे समय में आचारसंहिता लागू रहने से योजना से संबंधित कोई भी चर्चा घोषणा नहीं की जा सकती है।

## लांजी ब्लास्ट का आरोपी सावन टुटी केरल से धरया

**CHAIBASA :** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए आईडी विस्फोट मामले में फरार नक्सली सावन टुटी उर्फ सबन टुटी को केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मार्च 2021 में हुए उस हमले से जुड़ी है, जिसमें झारखंड जगुआर बल के तीन जवान शहीद हुए थे और तीन अन्य घायल हो गए थे। एनआई के अनुसार, सावन टुटी सरायकेला-खरसावां जिले का निवासी है और 2021 से फरार चल रहा था। उसे झारखंड व्हायर केस में लंबे समय से तलाशा जा रहा था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो उसकी माओवादी गतिविधियों से जुड़ी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। लांजी जंगल में हुए डायरेक्शनल लैंडमार्क विस्फोट की जांच एनआई ने टैकओवर की थी। इस मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी अनल दा उर्फ पतिराम मांडी समेत 33 नामजद नक्सलियों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 20अप्रैल 2025 अज्ञात लोगों को भी आरोपी सूची में शामिल किया गया है। 4 मार्च 2021 को हुए इस विस्फोट में झारखंड जगुआर बल के 3 जवानों ने शहादत दी थी।

## सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान बनाएगी एनआईटी-कालीकट

## PHOTON NEWS JSR :

झारखंड में सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान के निर्माण की प्रक्रिया अब रफता पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में एनआईटी कालीकट केरल की सात सदस्यीय टीम जमशेदपुर के दौरे पर आई है। टीम ने बुधवार को मानगो नगर निगम और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान को लेकर मंथन किया गया। गौरतलब है कि झारखंड के 10 नगर निगमों में यह एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एनआईटी-कालीकट (केरल) को तकनीकी सहयोग के रूप में चयनित किया गया है। 13 अक्टूबर को नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, रांची में



बैठक करती एनआईटी व नगर निकाय की टीम

● फोटोन न्यूज

एमओयू एक्सचेंज हुआ था। इस अवसर पर एकदिवसीय कार्यशाला भी हुई, जिसमें सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान की रूपरेखा और सर्वे कार्यों की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि इस योजना के बनने से शहरी क्षेत्र में आजीविका से जुड़ी वास्तविक स्थिति वर्तमान चुनौतियों, सतत रोजगार अवसर, रांची उन्मूलन और आजीविका संवर्धन जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। एनआईटी-कालीकट की टीम ने बताया कि नवंबर से मानगो एवं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस मौके पर एनआईटी कालीकट के प्रोफेसर, सीएमएम, सीओ और सीआरपी सहित सात सदस्यीय प्रतिनिधि दल उपस्थित था।

## उपचुनाव भवन निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश, अग्निशमन दल व एंबुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था

## घाटशिला में हेलीपैड के लिए सियासी दलों को खर्च करने पड़ेंगे 35,637 रुपये

## MUJTABA RIZVI @ JSR :

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। चुनाव के दौरान अगर किसी सियासी दल को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सभा करनी होगी तो इसके लिए उनके स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर कहां उतराया, इसका भी प्रबंध जिला प्रशासन ने कर लिया है। सियासी दलों की सूचना पर भवन निर्माण हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाएगा। दो तरह के हेलीपैड बनाए जाएंगे। हेलीपैड के इस्तेमाल के बदले में सियासी दल को शुल्क देना होगा। जिला प्रशासन ने शुल्क चार्ज बुधवार को जारी कर दिया है। भवन निर्माण दो तरह के हेलीपैड बनाएगा। एक ऐसा हेलीपैड होगा, जिसमें बैरिकेडिंग के साथ ही सारी



सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, बिना बैरिकेडिंग वाला हेलीपैड भी तैयार किया जाएगा। बिना बैरिकेडिंग के बनाया जाने वाला हेलीपैड सस्ता पड़ेगा। जबकि, बैरिकेडिंग के साथ बना हेलीपैड महंगा होगा। बैरिकेडिंग के साथ बनने वाले हेलीपैड के लिए राजनीतिक दलों को 35 हजार 637 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें हेलीपैड का शुल्क 27 हजार 937 रुपये रखा गया है। जबकि, एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये और अग्निशमन दल के लिए

6200 रुपये प्रति छह घंटा के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। बिना बैरिकेडिंग वाले हेलीपैड के लिए कुल 15 हजार 242 रुपये लिए जाएंगे। इसमें हेलीपैड का 7542 रुपये शुल्क है। एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये और अग्निशमन दल के लिए प्रति छह घंटे 6200 रुपये का शुल्क इसमें शामिल है। अगर किसी सभा में छह घंटे से अधिक का समय लग रहा है तो अग्निशमन दल का शुल्क अलग से लिया जाएगा। अगर कोई सियासी दल किसी निजी जमीन पर हेलीपैड बनवाना चाहता है तो उसे जमीन के मालिक से एनओसी लेनी होगी। जमीन का क्रियाय सियासी दल ही भुगतान करेगा। सरकारी जमीन पर हेलीपैड बनाने से पहले सियासी दल को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

## ओडिशा से जमशेदपुर लाए जा रहे 10.40 लाख रुपये जल

## JAMSHEDPUR :

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बुधवार को रसुनचोपा चेकनाका का मुआयना किया और चुनावी निगरानी को लेकर जारी वाहन जांच अभियान की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस ने एक कार से 10 लाख 40 हजार रुपये बरामद किए। रुपये ओडिशा से जमशेदपुर लाए जा रहे थे। बरामद रुपये निर्वाचन के व्यय कोषांग को भेजे जाएंगे, जो इस बात की जांच करेगा कि इस राशि का उपयोग चुनाव में होना था या नहीं। उसके अनुसार कारवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह दो दिनों में दूसरी बड़ी बरामदगी है। इससे पहले 13



ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग की उपस्थिति में वाहन की जांच करते पुलिसकर्मी

अक्टूबर को चेकनाका पर 12 लाख 28 हजार 400 रुपये जब्त किए गए थे। इस तरह, अब तक कुल 22 लाख 68 हजार 400 रुपये बरामद किए जा चुके हैं।

## तीन अभ्यर्थियों ने खरीदा नामांकन पत्र

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को तीन अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। इनमें विकास हेम्रम (ग्राम दिग्डी, जादुगोड़ा), पंचानन सोरेन (ग्राम भाडुआ, धालभूमगढ़) व पार्वती हांसदा (ग्राम मेड़िया, बड़ा बस्ती, मुसाबनी) शामिल हैं। इससे पहले झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन सहित पांच लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा था।

## मतदाताओं को प्रभावित करने की जरूरत दें सूचना : उपायुक्त

## JAMSHEDPUR :

जिले के आम नागरिकों एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्याथी ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आकर तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। कोई भी व्यक्ति यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी मतदाता को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई रिश्वत देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुमाने या दोनों से दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कृति पहुंचाने की धमकी देता है या डराने-धमकाने का प्रयास करता है, तो वह भी एक



वर्ष तक के कारावास या जुमाने, या दोनों से दंडनीय है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत न लें और न दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा रिश्वत की पेशकश की जाती है या मतदाताओं को डराने-धमकाने से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला निबंधन कक्ष के फोन नंबर : 0657-2440111, 0657-2221717, 0657-2221718 पर दें। आपकी सजगता और सहयोग से स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।



## सर क्रीक को लेकर रहना होगा सचेत

सर क्रीक क्षेत्र भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सैन्य जमावड़े को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है, जो गुजरात में कच्छ के रण को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सर क्रीक विवाद की जड़ें 1908 से जुड़ी हैं, जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को लेकर असहमति उत्पन्न हुई। ब्रिटेन प्रेसिडेंसी द्वारा 1914 में एक प्रस्ताव के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने एक अस्पष्टता पैदा कर दी। प्रस्ताव के एक खंड में सुझाव दिया गया कि सीमा क्रीक के बाहरी किनारे की ओर स्थित है, जबकि दूसरे में अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया, जिसके अलग निहितार्थ थे। यह मुद्दा 1965 के सप्तसत्र संघर्ष के बाद फिर से उभरा, जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया। 1968 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रण के 90 प्रतिशत हिस्से पर भारत के दावे को बरकरार रखा, लेकिन सर क्रीक सीमा अनसुलझी रही। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान जोर देता है कि यह क्रीक के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अंतर निर्धारित करता है कि समुद्री सीमा अरब सागर में कैसे फैली हुई है, जो संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और दोनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अरबों डॉलर के सामुद्रिक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है। साल 1989 से भारत और पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने के लिए टोस धरत के बिना छह दौर की चर्चाएं कर चुके हैं। पाकिस्तान जोर देता है कि समुद्री सीमा के लिए आधार स्थापित करने के लिए पहले क्रीक में सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों को जोड़ता है। वहीं भारत ने प्रतिक्रिया के तहत एक प्रस्ताव रखा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों और राजनीतिक अविश्वास ने कार्यान्वयन को रोक दिया है। यह भारत के अपने अन्य पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के सफल समाधान के बिल्कुल विपरीत है। श्रीलंका के साथ 1974 और 1976 में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने मालदीव के साथ त्रिबिंदु से लेकर पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में 200 समुद्री मील की सीमा तक फैली 288 किलोमीटर की समुद्री सीमा स्थापित की गई। बांग्लादेश के साथ दशकों की असफल बातचीत के बावजूद विवाद अंततः संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानूनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया। 2014 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने बंगाल की खाड़ी में विवादित 25,602 वर्ग किलोमीटर में से 19,467 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश ने इस बाध्यकारी निर्णय को स्वीकार किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तब समुद्री सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से संभव है। सर क्रीक पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची इस विवादित सीमा से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां इसका प्राथमिक नौसैनिक अड्डा है। यहां भारतीय नौसैनिक उपस्थिति पाकिस्तान की व्यावसायिक जीवन रेखा और सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरों में डालती है। भारत के लिए सर क्रीक को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह और क्षेत्र को घुसपैठ गलियारा बनने से रोकने के लिए भी यह जरूरी है। सर क्रीक पर उठे विवाद को नए सिरे से 2019 के बाद के सैन्य गतिरोध और आपरेशन सिंदूर के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण जैसे कि स्वदेशी विमानवाहक पोत, उन्नत पनडुब्बियां और बड़ी हुई तटीय निगरानी ने समुद्री शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया है। पाकिस्तान इसके जरिये नौसैनिक रणनीति को तेज करना चाहता है। वह उन्नत पनडुब्बियां और जहाजरोधी मिसाइलें प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य सहायता का लाभ उठाना चाहता है। सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी दुस्साहसिक कार्रवाई उसे फौजदारी तक पहुंचाने पर मजबूर कर सकती है। सर क्रीक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ नियमित गश्त भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है। ये गश्त एक दोहरे उद्देश्य को पूर्ति करती हैं। इससे दोनों देश विवादित जल पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और दोनों देशों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार करने से रोकते हैं। फिलहाल यह भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। सर क्रीक पर भारत की सीमाओं की हड़ता यह संदेश देती है कि राजनैतिक सर्वोपरि है और हर इंच भूमि की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान यदि नए सिरे से राजनैतिक पहल करे, आतंकवादियों को समर्थन बंद कर दे और अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी दिखाए तो सर क्रीक विवाद का समाधान निकल सकता है।

### ANALYSIS



प्रमोद भार्गव

दूरचल में समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारत विकास की दृष्टि से पीछे रहा है। उन तटीय क्षेत्रों पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो देश के लिए नई आर्थिक और चीन जैसे देश से चुनौती के लिए सामरिक दृष्टि से अहम हो सकते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इस नाते अछूता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस क्षेत्र को एक तो प्रसिद्ध सेल्युलर जेल के नाम से जानते हैं, जो अब राष्ट्रीय स्मारक है। दूसरे उन जनजातियों के लिए जानते हैं, जो आज भी भारत की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। नतीजतन अपनी परंपरागत प्राकृतिक अवस्था में रहकर प्रकृति से ही गुजर बसर कर रही हैं। किंतु, अब इस उपेक्षित क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। सिंगापुर की तर्ज पर निकोबार के तट का विकास केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में धन का निवेश करके महान निकोबार द्वीप परियोजना (जीएनआई) के अंतर्गत कर रही है। 75 हजार करोड़ की इस बृहद परियोजना के तहत कई परिवोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। निकोबार द्वीप समूह 10 हजार 44 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह (ट्रांसशिपमेंट पोर्ट) का निर्माण करने की योजना निर्माणधीन है। यह बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगा। विकास के इसी क्रम में चेन्नई से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2022 को कर चुके हैं। देश की मुख्य भूमि से 2312 किमी दूर तक तार को समुद्री जल के भीतर बिछाया गया है। इस कटिन और चुनौतीपूर्ण कार्य में 1224 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस बंदरगाह को समुद्री जलमार्ग की प्रमुख

महान निकोबार द्वांचागत परियोजना के विकास में काँग्रेस नेता सोनिया गांधी रोड़ा बन रही हैं। इस परियोजना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कहा है कि शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का अस्तित्व इस परियोजना के चलते दांव पर है। भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश की अनुमति नहीं दे सकती। हमें न्याय के इस उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ इस विश्वासघात के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। इसके पहले राहुल गांधी ने भी जनजातीय मामलों के मंत्री जुगल ओराम को लिखे पत्र में इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी। लिखबंदा देखिए, मां-बेटे को एक अलग संरचनात्मक विकास परियोजना पर तो आपत्ति है, लेकिन उन्हें कभी आदिवासियों के ईसाई और इस्लामीकरण पर आपत्ति नहीं होती है। दोनों के मुख से कभी नहीं सुना गया कि जबुरन धर्मांतरण कदाई न्यायसंगत नहीं है। दूरचल में समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारत विकास की दृष्टि से पीछे रहा है। उन तटीय क्षेत्रों पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो देश के लिए नई आर्थिक और चीन जैसे देश से चुनौती के लिए सामरिक दृष्टि से अहम हो सकते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इस नाते अछूता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस क्षेत्र को एक तो प्रसिद्ध सेल्युलर जेल के नाम से जानते हैं, जो अब राष्ट्रीय स्मारक है। दूसरे उन जनजातियों के लिए जानते हैं, जो आज भी भारत की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। नतीजतन अपनी परंपरागत प्राकृतिक अवस्था में रहकर प्रकृति से ही गुजर बसर कर रही हैं। किंतु, अब इस उपेक्षित क्षेत्र



की तस्वीर बदलने जा रही है। सिंगापुर की तर्ज पर निकोबार के तट का विकास केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में धन का निवेश करके महान निकोबार द्वीप परियोजना (जीएनआई) के अंतर्गत कर रही है। 75 हजार करोड़ की इस बृहद परियोजना के तहत कई परिवोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। निकोबार द्वीप समूह 10 हजार 44 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह (ट्रांसशिपमेंट पोर्ट) का निर्माण करने की योजना निर्माणधीन है। यह बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगा। विकास के इसी क्रम में चेन्नई से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2022 को कर चुके हैं। देश की मुख्य भूमि से 2312 किमी दूर तक तार को समुद्री जल के भीतर बिछाया गया है। इस कटिन और चुनौतीपूर्ण कार्य में 1224 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस बंदरगाह को समुद्री जलमार्ग की प्रमुख

गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैसे भी यह क्षेत्र दुनिया के कई पोतांतरण बंदरगाहों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धा दूरी पर स्थित है। बदलती जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि जिस देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का नेटवर्क और कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, इक्कीसवीं सदी के व्यापार में वही देश अग्रणी रहेंगे। ऐसे में इस दूरचल में द्वांचागत सुविधाएं बढ़ेंगी तो अंतर्गत का विकास तो होगा ही, अन्य भारतीयों से समरसता भी बढ़ेगी। एक बार जब यह बंदरगाह बन जाएगा तो यहां बड़े-बड़े देशी-विदेशी जहाज भी रुकने लगेंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को नए रोजगार पैदा होंगे। अकुशल मजदूरों को भी काम-धंधा मिलेगा। इस द्वीप पर विकसित किए जा रहे माल-परिवहन के दो रणनीतिक कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल के दो भौगोलिक फायदे होंगे। पहला, यह स्वस्त पूर्वी-पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय जहाज रानी मार्ग के निकट है। अतएव शुरू होने के बाद यह पोतांतरण की बेहतर सुविधा देगा, नतीजतन व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरे, इस क्षेत्र में आधुनिक ढंग से निर्मित

जहाजों से माल उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं बंदरगाह पर उपलब्ध होंगी, इस कारण बड़े जहाजों की आवाजाही बढ़ेगी। फिलहाल भारत के ज्यादातर बंदरगाहों पर बड़े जहाज बंदरगाह के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतएव छोटे जहाजों में माल उतार व लादकर गंतव्य तक पहुंचने का अतिरिक्त श्रम व मजदूरी लगती है। इस प्रक्रिया में माल का खर्च बढ़ जाता है। अंडमान-निकोबार प्रशासन ने कुछ समय पहले ही महान निकोबार द्वीप की दक्षिणी खाड़ी में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र विकसित करने के लिए कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल के लिए प्रक्रिया आरंभ की है। इससे भारतीय पोत परिवहन को कोलांबो (लंका), सिंगापुर और मलेशिया के बलांग बंदरगाह में पोतांतरण का नया विकल्प हासिल होगा। दरअसल वर्तमान में भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए एक हट्ट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही वैश्विक स्तर पर विनिर्माण और वस्तुओं की आपूर्ति की कड़ी में अहम भागीदारी कर खुद को एक विश्वसनीय कारोबारी के रूप में स्थापित करने में लगा है। इससे भारत को समुद्र में देशी-विदेशी यातायात और समुद्री संपदा से

आर्थिकी और रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे। चीन के निकट होने के कारण इस बंदरगाह का सामरिक रूप में भी रणनीतिक व कूटनीतिक उपयोग किया जा सकेगा। विकास पूर्ण हो जाने पर यहां मछली पालन एक्वाकल्चर और सीवीड फॉर्मिंग का कारोबार बढ़ेगा। भारत के व्यापारी ही नहीं दुनिया के कई देश इस परिप्रेक्ष्य में व्यापार की बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं। इस दृष्टि से पोर्टब्लेयर में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी, जिसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। गुजरात के भावनगर स्थित केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है। भारत में लगभग 8118 किमी समुद्र तटीय क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में मछलियों और समुद्री शैवाल व एल्गी का बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री ह्यमत्स्य संपदा योजनाद्वारा के अंतर्गत 640 करोड़ रुपये इस संपदा को सुगम खाद्य पदार्थ में बदलने के लिए दिए गए हैं। अंडमान-निकोबार से लेकर समुद्र तटीय मछुआरों की हालत भी मैदानी क्षेत्रों में फैले गरीब व पराश्रित किसानों जैसी ही है। इन तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले मछुआरों की संख्या करीब आठ करोड़ है। बड़ी नदियों से मछली पकड़ कर गुजारा करने वाले भी करीब तीन करोड़ मछुआरे हैं। गोया, तय है अंडमान-निकोबार क्षेत्र में तटवर्ती मछुआरों को इस क्षेत्र के विकास का सीधा लाभ मिलेगा। मछली और सीवीड का कारोबार बढ़ेगा, जिससे इस समुदाय की समृद्धि बढ़ेगी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का निकोबार क्षेत्र आरक्षित जैवमंडल (बायोस्फीयर) क्षेत्र में आता है। इसे 2013 में विशेष जैवमंडल का दर्जा दिया गया था।

## समय के साथ बदल रहा डाक विभाग

वर्ष 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन करने के लिए विस्वडरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1969 में जापान के टाकियो शहर में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन किये जाने की घोषणा की गयी थी। 01 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय मेल ट्रेफिक के आधार पर भारत शुरू से ही प्रथम श्रेणी का सदस्य रहा है। भारत में डाकघर का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से शुरू होता है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 में पहली डाक व्यवस्था स्थापित की। वीरन हेरिस्टंस ने 1774 में कोलकाता में पहला डाकघर खोला और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक राष्ट्रीय डाक सेवा की शुरूआत की। आज भारतीय डाक दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है जो बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाओं के

साथ आम आदमी का भरोसेमंद साथी है। 01 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक विभाग की स्थापना के साथ भारत में पहली बार डाक टिकट भी जारी किया गया था। विश्व डाक दिवस का मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 150 से ज्यादा देशों में विविध तरीकों से विश्व डाक दिवस आयोजित किया जाता है। भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल पहले अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की पहल की थी। उन्होंने भारतीय डाक को नया रूप-रंग दिया। पर अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। हमारे देश में पहले डाक विभाग का इतना अधिक महत्व था कि फिल्म्स तक में डाकिये पर कई महशूर गाने फिल्माए गए हैं। मगर अब नजारा पूरी तरह से

बदल चुका है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने डाक विभाग के महत्व को बहुत कम कर दिया है। आज लोगों ने हाथों से चिट्ठियां लिखना छोड़ दिया है। अब ई-मेल, वॉट्सएप व सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से मिन्टों में लोगों में संदेशों का आदान-प्रदान हो जाता है। आज डाक में लोगों की चिट्ठियां तो गिनती की ही आती हैं। मनीऑर्डर भी बंद ही हो गए हैं। मगर डाक से अन्य सरकारी विभागों से संबंधित कारजात, बैंकों व अन्य संस्थानों के प्रपत्र काफी संख्या में अने से डाक विभाग का महत्व फिर से एक बार बढ़ गया है। डाक विभाग कई दशकों तक देश के अंदर ही नहीं, बल्कि एक देश से दूसरे देश तक सूचना पहुंचाने का सर्वाधिक विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन रहा है। लेकिन, इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के बढ़ते दबदबे और फिर सूचना तकनीक के नए माध्यमों के प्रसार के कारण डाक विभाग की भूमिका लगातार कम होती गई है। वैसे इसकी प्रासंगिकता पूरी दुनिया में आज भी बरकरार है। भारत में डाक

विभाग के महत्व को महशूर शायर निदा फाजली के शेर -सीधा-साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे अंसे और मुस्कान- से समझा जा सकता है। शासन निदा फाजली ने जब यह शेर लिखा था, उस वक्त देश में संदेश पहुंचाने का डाक विभाग ही एकमात्र साधन था। डाकिये के थैले में से निकलने वाली चिट्ठी पढ़कर कोई खुश होता था तो कोई दुखी। कुछ वर्ष पूर्व तक डाक विभाग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। गांव में जब डाकिया आता था तो बच्चे-बूढ़े सभी उसके साथ डाक घर की तरफ इस उत्सुकता से चल पड़ते थे कि उनके भी किसी परिजन की चिट्ठी आएगी। डाकिया जब नाम लेकर एक-एक चिट्ठी बांटना शुरू करता तो लोग अपनी या अपने पड़ोसी की चिट्ठी ले लेते व उसके घर जाकर उस चिट्ठी को बड़े चाव से देते थे। उस वक्त शिक्षा का प्रसार ना होने से अक्सर महिलाएं अनपढ़ होती थी। इसलिए चिट्ठी लाने वालों से ही चिट्ठियां पढ़वाती थी थीं और लिखवाती थी थीं। कई बार चिट्ठी

पढ़ने-लिखने वाले बच्चों को इनम स्वरूप कुछ पैसा या खाने को गुड़, बताशे भी मिल जाया करते थे। इसी लालच में बच्चे ज्यादा से ज्यादा घरों में चिट्ठियां पहुंचाने का प्रयास करते थे। उस वक्त गांवों में बैंक शाखा नहीं होती थी। इस कारण बाहर कामने गए लोग अपने घर पैसा भी डक में मनीऑर्डर देकर लाया करते थे। मनीऑर्डर देने डाकिया स्वयं प्राप्तकर्ता के घर जाता था व भुगतान के वक्त एक वाक के भी हस्ताक्षर करवाता था। डाक विभाग अति आवश्यक संदेश को तार के माध्यम से भेजता था। तार की दर अधिक होने से उसमें संक्षिप्त व जरूरी बातें ही लिखी जाती थीं। तार भी साधारण और जरूरी होते थे। जरूरी तार की दर सामान्य से दोगुनी होती थी। देश में पहली बार 11 फरवरी 1855 को शुरू हुई तार सेवा को सरकार ने 15 जुलाई 2013 से बंद कर दिया है। इसके साथ ही डाक विभाग में आएंगे, रजिस्टर्ड डाक सेवा को भी 01 अक्टूबर 2025 से स्प्रीड पोस्ट में विलय कर दिया है। भारतीय डाक विभाग पिनकोड नंबर (पोस्टल

इंडेक्स नंबर) के आधार पर देश में डाक वितरण का कार्य करता है। पिनकोड नंबर का प्रारंभ 15 अगस्त 1972 को किया गया था। इसके अंतर्गत डाक विभाग द्वारा देश को नौ भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। संख्या 1 से 8 तक भौगोलिक क्षेत्र हैं व संख्या 9 सेना की डाक सेवा को आवंटित किया गया है। पिन कोड की पहली संख्या क्षेत्र दूसरी संख्या उपक्षेत्र, तीसरी संख्या जिले को दर्शाती है। अंतिम तीन संख्या उस जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती है। डाक विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीबी) शुरू किया है। देश के हर व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के क्रम में यह एक बड़ा विकल्प होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देशभर में बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस के माध्यम से देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क अस्तित्व में आएगा, जिसकी हर गांव तक मौजूदगी होगी। इन सेवाओं के लिए पोस्टल विभाग के 11000 कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देंगे।

## Social Media Corner

सब के हक में...

मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री रैता ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। वे एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा सहयोग वर्षों तक जारी रहा। भारत, हमारी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था। यह भारत-केन्या संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों में परिलक्षित होता था। वे विशेष रूप से आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर इनके सफलताप्रक प्रभाव को देखा था। इस दुःख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)



सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर आठ निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि 8-10 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं, और अब खनन माफियाओं के दलाल उनके परिजनों को पैसे देकर गुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस गोरखधंधे के हिस्सेदार पुलिस, स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने, यानी केस दर्ज करने, दौषियों पर कार्रवाई करने और लापता मजदूरों को बचाने के बजाय न्याय गायब कराने और पीड़ित परिवारों को गुप कराने की मुहिम में शामिल बताए जा रहे हैं। (बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

## कफ सिरप कांड से गंभीर सबक लेने की जरूरत

कफ सिरप से नौनिहालों की मौत का सिलसिला थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हालांकि ताबडतोड़ छापेमारी, धरपकड़, गिरफ्तारियां भी साथ-साथ हो रही हैं। इस कांड की चर्चा भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। दिल दहला देने वाली कफ सिरप की घटना के गर्भ से उपजे इस अक्षय्य अपराध ने भारत में कुकुरमुत्तों की तरह सक्रिय नकली फार्मा कंपनियों की ओर दुनिया का ध्यान करा दिया है। जाली फार्मा कंपनियों का जाल इस समय देश में फैला हुआ है। नकली दवाइयों के निर्माण में अभी तक चीन बदनमा था। पर, तीन वर्ष पहले जब भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित नकली कफ सिरप के पीने से अफ्रीकी देशों में 50 से भी अधिक बच्चों की जब मौत हुई तो दुनिया की नजरों में भारत आ गया। ताजा घटना ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। विदेशी अखबारों में भी कफ सिरप कांड की खबरें प्रमुखता से छप रही हैं। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों की साख को काफी धक्का पहुंचा है। खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ देशों ने पहले से करार दवाइयों के ऑर्डरों को निरस्त करना भी शुरू कर दिया है। अफ्रीकी देश तो पहले से ही चौकन्ने हैं। भारत में बनी कफ सिरप पीकर जब अफ्रीकी बच्चों की मौत हुई, तब इसे लेकर केंद्र सरकार ने जुमानें सहित तमाम कठोर कदम उठाए थे। कई फार्मा

कंपनियों को ब्लैकलिस्ट और कड़ियों के लाइसेंस निरस्त किए गए थे। लेकिन, दोबारा ऐसी कंपनियां सक्रिय हो गई हैं जिससे अफ्रीका जैसे घटना की पुनरावृत्ति भारत में हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कथित रूप से कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी खबरें आती हैं कि नकली दवा के सेवन से मरीजों की किडनियां खराब हुईं, जिससे उनकी मौत भी हुई। सभी जानते हैं कि भारत में जेनेरिक दवाओं के वितरण में बड़ा घपला है। आमजन से लेकर सरकारों भी इस सच्चाई से वाकिफ होती हैं कि दवा क्षेत्र में बड़े माफिया सक्रिय हैं, लेकिन इनके खिलाफ की गई हर कार्रवाई बौनी साबित हुई है। भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता काफी समय से सवालों के घेरे में है। जेनेरिक दवाओं के वितरण में भारत में करीब 15 से 20 हजार औषधि केंद्र संचालित हैं। जबकि, इनकी संख्या इस साल के अंत तक 25 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन इनके भीतर कितना गड़बड़झाला है, जिसकी भनक अभी तक को जरा भी नहीं है। फार्मा कंपनियों और कमीशनखोरों को अच्छे से पता होता है कि मरीज दवाओं के नाम पर हर वह चीज गटक जाएंगे जो उन्हें दी जाएगी और उन्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। कमोबेश, हो भी कुछ वैसा ही

रहा है। बहरहाल, मौजूदा कफ सिरप कांड ने न सिर्फ स्वास्थ्य सिस्टम को हिलाया है, बल्कि पूरा देश सोचने पर मजबूर है। कफ सिरप के नाम पर भारत में बीते कई वर्षों से मासूमों को जहर पिलाया जा रहा है। भांडा देने फूट में समा गए। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। दवाओं के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ से बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। गलत दवा लिखने वाले चिकित्सकों पर कड़ा एक्शन हो और मुनाफा कमाने के भूखे विक्रेताओं पर सरकारी चाबुक चले- ऐसी कल्पना सभी करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य ऐसा होता नहीं। भारत में 3000 से अधिक दवा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास 10,500 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। यह उद्योग जेनेरिक दवाओं के निर्माण और आपूर्ति पर केंद्रित है। दवा निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अपने काले कारनामों के चलते ये फार्मा कंपनियां सभी की नजरों में आ गई हैं। भारतीय फार्मा उद्योग का कुल बाजार साल 2030 तक 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर और साल 2047 तक 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय दवा कंपनियों से केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025 में करीब 11 फीसदी अधिक राजस्व हासिल हुआ।

## Gaza conundrum: How Hamas gained despite defeat

The Gaza war, now tapered into an awkward ceasefire, has left behind devastation beyond imagination. Israel fought with overwhelming force, Hamas remains battered but not erased, and the world once again confronts the familiar question that has shadowed the region for decades: who really gains when the dust settles? It may sound counterintuitive, but in the political and psychological sense, Hamas appears to have secured what strategists call 'perceptual victory', even as Gaza lies in ruins. The October 2023 attack by Hamas was a meticulously planned but morally indefensible act of terror that shocked even those sympathetic to the Palestinian cause. The deliberate targeting of civilians is beyond justification. Hamas likely believed that only such a drastic act could revive global focus on a fading cause. With the Abraham Accords expanding and Saudi-Israeli normalisation on the horizon, the Palestinian issue risked permanent marginalisation. Strategically, the perception was correct; the method, however, remains unacceptable to the civilised world. For Israel, the response was shaped by two impulses. The first was the national need for retribution—a visceral reaction to the scale of the assault, necessary to preserve deterrence and restore confidence among its citizens. The second was political. Benjamin Netanyahu's survival depended on projecting absolute resolve. A restrained response would have been interpreted domestically as weakness and internationally as loss of moral ascendancy. Yet, the ferocity of the Israeli retaliation, which blurred the line between combatant and civilian, ended up achieving the reverse—moral erosion in the eyes of much of the world. Had Israel opted for a more selective approach—differentiating clearly between Hamas's armed elements and Gaza's civilian population—the story might have been different. But even then, the outcome may not have served Israel's core objectives. Precision targeting alone could hardly dismantle an organisation deeply embedded in a social and religious network. In asymmetric warfare, the stronger side is always constrained by its strength. Ethical restraint can appear a weakness; overwhelming force breeds resentment. Israel faced an unenviable choice, as either path would have led to strategic frustration. What followed was a campaign that achieved tactical success but strategic ambiguity. Hamas's command structures were disrupted but not destroyed. Its fighters melted away into the urban maze. Its political narrative, meanwhile, gained renewed currency. Images of devastation and humanitarian suffering flooded global consciousness, shifting public opinion in many countries away from Israel's narrative of self-defence. The international community's sympathy, initially with Israel, slowly tilted towards the Palestinian people. This shift was not about ideology, but about the human cost that became impossible to ignore. The paradox of modern conflict is clear. Wars are judged less by territory gained and more by legitimacy sustained. Israel's moral authority, once grounded in its democratic ethos and history of persecution, now faces growing challenge. Much of the Global South views Gaza through the lens of excessive force, while younger Western audiences question Israel's proportionality. Hamas, though condemned for terror, gains indirectly from this erosion of Israel's moral standing.

## A new blot on Indian pharma

Deaths caused by contaminated cough syrups lay bare a dysfunctional drug regulation system

THE spate of deaths of children, caused by the consumption of cough syrups adulterated with a toxic industrial chemical, has brought the focus back on India's dysfunctional drug regulation system. In recent years, several such tragic incidents have occurred in India and abroad, involving drugs manufactured in this country. Our response is the same every time — deaths blamed on contaminated or substandard drugs, inquiries by state and Central governments, raids on some manufacturing units here and there, reporting of non-compliance of norms, suspension of manufacturing licences of some units, a directive from the health ministry to states to implement regulatory norms 'strictly' and a return to 'business as usual' in no time. No heads roll, no changes are made in the regulation, vacancies in drug regulatory bodies are not filled, no errant units are shut permanently, and nobody bothers to share findings of probes ordered into earlier episodes.

The culprits that make cough syrups toxic are well known by now: diethylene glycol (DEG) and ethylene glycol. Toxic effects of the two contaminants include abdominal pain, vomiting, diarrhoea, inability to pass urine, headache, altered mental state and acute kidney injury, which may lead to death. Apparently, the two chemicals get mistakenly used while manufacturing cough syrups, especially in syrups that use agents like propylene glycol and polyethylene glycol. After dozens of children died in The Gambia, Uzbekistan, Cameroon, Iraq and other countries after consuming 'made in India' products, the World Health Organisation (WHO) has been warning national regulatory and health authorities to notify if such products were detected in their respective countries. The agency has advised national authorities to test raw materials for the presence of DEG before use in medicines. DEG is responsible for the cough syrup deaths in Chhindwara, Madhya Pradesh. It is pathetic that cough syrup manufacturers are so careless that their products get contaminated with deadly toxins. It only goes to show that they are not adhering to mandatory Good Manufacturing Practices (GMP) rules. Are they not following GMP, or is the government giving them a long rope? It is both. After every death due to contaminated drugs, there is talk of implementing GMP or making them stricter. The moment this is done, industry associations representing small and medium drug manufacturers seek

time to implement GMP rules or seek relaxations, citing the excuse that they do not have the capacity to implement the norms. The government, too, is sympathetic, as strict implementation or closure of non-compliant units could hurt its 'Make in India' programme. After the deaths of 68 children in The Gambia, Indian agencies even accused the WHO of not following procedures and saw a conspiracy to defame Indian exports. After the Chhindwara incident, the Drug Controller General of India has reiterated the need for drug manufacturers to comply with the Revised Schedule M of GMP. As per an official press release, he has noted that "certain firms which applied for the government's infrastructure upgradation scheme have been given an

A review of product quality is required, involving the analysis of data from batch records and critical process parameters. Manufacturers must retain samples of intermediate and final products for potential retesting.

So, norms are there, they are revised to make them more stringent, but there is no will to implement them. Central and state drug control authorities, tasked with enforcing the norms, are short of staff or are kept deliberately understaffed. An umpteen number of expert panels, review committees and parliamentary panels have pointed this out in the past two decades, but the situation on the ground remains unchanged. Things are especially bad in states like Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu and Himachal Pradesh, which have a huge concentration of drug manufacturing units.

Drug regulation in India needs a fundamental change. The focus of drug regulatory authorities and the government is on the drug and pharmaceutical industry and not on consumer or patient interest. Norms are allowed to be lax, or non-compliance is tolerated to protect the industry. Otherwise, there is no reason DEG should have killed Indian children after the chemical was found responsible for the deaths of kids in The Gambia and other countries exporting cough syrups made in India. There should have been a nationwide crackdown on all manufacturers of cough syrups, and those found using DEG should have been identified and punished. All this did not happen, resulting in the Chhindwara deaths.

The 59th report of the Parliamentary Committee on Health and Family Welfare, presented in Parliament in

2012, had stated that "most of the ills besetting the system of drug regulation in India are mainly due to the skewed priorities and perceptions of the drug regulator. For decades together, it has been giving primacy to the propagation and facilitation of the drugs industry, due to which, unfortunately, the interest of the biggest stakeholder, i.e. the consumer, has never been ensured."

The panel recommended that the mission statement of the Central drug organisation should state that it was solely meant for public health. The statement was changed, but it has remained a cosmetic change, going by the recurring incidents of substandard and adulterated drugs killing people and industry interests taking precedence over people's health.



extension till December 2025" and urged states to strictly implement the revised GMP norms. It implies that as of now, the new schedule of GMP is not being implemented. The new schedule was introduced after an international uproar over deaths caused by India-made cough syrups in several countries. It became effective for large firms in June 2024, but small and medium-sized manufacturers (having a turnover of less than Rs 250 crore) were given time till December 2025, although most of the contaminated drugs were produced by such firms. The turnover limit was fixed in such a way as to cover a bulk of the manufacturers. Schedule M requires drug manufacturers to adhere to practices such as the Pharmaceutical Quality System, quality risk management and computerised storage systems.

## Name more stands after women cricket greats

The women's game has experienced a significant upward trend in recent years, so has the fame of some of its players

Sunday will go down as a red-letter day in women's cricketing history for more reasons than one. Alyssa Healy of Australia accomplished the greatest run chase in women's one-day cricket against India at Visakhapatnam. If the ending of the World Cup match was awe-inspiring, its beginning at the YSR Reddy Andhra Cricket Association-VDCA stadium was about grateful remembrance. For only the third time in India, a stadium got stands and gates named after legendary women cricketers—a stand after former India captain Mithali Raj and a gate after Andhra Pradesh and India wicketkeeper-batter R Kalpana. Only two other venues in the country have honoured women cricketers in such a manner. In 2017, the Delhi District Cricket Association named two gates at what was then called the Feroz Shah Kotla stadium after former captain Anjum Chopra. Eight years down the line, the Cricket Association of Bengal honoured former captain and legendary pacer Jhulan Goswami with a stand at the Eden Gardens.

One cannot forget the hard work of legends who helped the women's game grow despite a severe shortage of money

and infrastructure. Inscripting their names permanently at facilities to be used by fans and cricketers can instil pride



and act as a great motivator. However, the Indian cricket board and its state affiliates can surely do more. Last year, selector Venkatesh Kalpana raised the issue that

Shantha Rangaswamy, India's first women's team captain, was not on the list of legends being honoured with stands at Bengaluru's M Chinnaswamy stadium. Last week, several former India and Mumbai cricketers wrote to the Mumbai Cricket Association urging to name a stand after ex-captain Diana Edulji. Smriti Mandhana, vice-captain of the present team, has added her voice to the growing demand.

Such memorialising through naming is a norm in India and men have shared most of the honours. However, it must be noted that as the women's game has experienced a significant upward trend in recent years, so has the fame of some of its players. This is evident from the crowds thronging the Women's World Cup venues—though the stadiums are not full, their numbers are significantly larger than in earlier years. Hopefully, as the World Cup attracts more attention as it rolls towards the semifinals, the Indian cricket board and state units will consider expanding the inclusive trend in naming.

## Serpent's gift: Fortune and The queer history of 'queer'

The evolution of the word's usage in today's constitutional jurisprudence represents a remarkable transformation from colonial criminalisation to constitutional affirmation.

Over the decades, as our constitutional courts came to be confronted with matters relating to homosexuality and the rights of persons from the third gender, the language employed by these courts evolved from clinical or derogatory to one of acceptance and affirmation. During this period, the natural meaning of the word 'queer', once used as a pejorative, has transformed into an inclusive umbrella identity, having been reclaimed by the LGBTQIA+ communities.

Equally, the evolution of the word's usage in today's constitutional jurisprudence represents a remarkable transformation from colonial criminalisation to constitutional affirmation, though its direct usage in judicial opinions still remains denotative, lexical and surprisingly limited. From the early colonial period to the late 20th century, 'queer' was mostly restricted in usage in the context of 'strange or odd'. That's the sense in which it was used by the Madras High Court at one of the many proceedings related to the infamous liquidation of Travancore National and Quilon Bank (1941)—"it did strike him as queer". One of the very first constitutional cases to employ the word was S B Trading Co (1951), where the Calcutta High Court observed about different classes of tenants, "[t]hey are not similarly circumstanced individuals and if the effects are queer as indeed they are, even they cannot be said to infringe the constitutional guarantee of equal protection". Decades later, when the Delhi High

Court delivered the famous judgement in Naz Foundation (2009), 'queer' was employed once: "When everything associated with homosexuality is treated as bent, queer, repugnant, the whole gay and lesbian community is marked with deviate and perversity." In its judgement on the appeal, the Supreme Court chose not to employ the word at all, except while extracting the high court's judgement.

Thereafter, the Supreme Court in Navtej Singh Johar (2018) showed a pronounced alteration in its jurisprudential stance, using the word to note that the "LGBTIQ movements focused on... the interplay of oppressions arising from being both queer and lower class". It also quoted a judge of the High Court of Australia who found the word queer was being "sometimes used generically, usually by younger people, to include the members of all sexual minorities". Thereafter, a significant change in attitude set in with the Supreme Court's judgement in Supriyo (2023), where the word is used liberally. In one footnote, the court even notes that the term "once pejoratively used to demean persons who engaged in 'deviant' sexual behavior or gender expressions, has been reclaimed by activists as a way of expressing pride in their devalued and marginalised identities, challenging majoritarian hetero-normativity".

In a recent judgement, however, a division bench of the Madras High Court found the term

discomforting. As the court correctly notes, dictionaries define queer as 'strange or odd' and the phrase 'queering one's pitch' means spoiling something. From the bench's standpoint, using terminology that inherently suggests abnormality to describe citizens seeking equal protection under law seems counterintuitive, even potentially



harmful. This perspective reflects a broader judicial responsibility: ensuring that legal language affirms dignity rather than diminishing it. What the court's analysis doesn't capture is the powerful history of linguistic reclamation that has transformed 'queer' from a slur to a symbol of pride and resistance. Identity in gay and lesbian theory has always been fraught. In the wake of the Stonewall movement in New York, openly gay and lesbian perspectives reshaped political, philosophical and literary debates—initially

through feminist critiques of patriarchy—before coalescing into queer theory by the late 1980s.

Early essentialist models of lesbian and gay identity—defining sexuality by strict, supposedly universal traits—ended up excluding those who didn't fit the mould, erasing intersecting factors like race and ethnicity, and treating identity categories as fixed rather than historically and socially constructed. Michel Foucault's examination of the historical construction of 'homosexuality' played a significant role in changing this. He argued that sexual identity arises from medical, legal, and social practices, rather than reflecting an innate category. His work underscores that modern sexual classifications are contingent inventions shaped by specific historical forces. Queer theory contested the rigid definitions, showing how those supposed 'essences' excluded anyone whose experience—shaped by race, subcultural affiliation, or other differences—did not conform to the norm. It also challenged the idea that identity categories are timeless and immutable, instead highlighting the historical and social forces that morph them. By embracing 'queer' as an open-ended term—defined by its departure from whatever norm holds sway—queer theory and LGBTQIA+ communities have created room for a wide array of self-definitions. It reminds us that identity is something we construct, not something prescribed.

## Sensex opens over 200 points higher, Nifty above 25,200; NTPC up 1%

New Delhi.(Agency)

Benchmark stock market indices opened higher on Wednesday as IT, auto, PSU bank and FMCG stocks gained in early trade. The S&P BSE Sensex added 322.86 points to 82,352.84, while the NSE Nifty50 gained 105.50 points to 25,250.55 as of 9:35 am. Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said that the drift in the market on lack of positive triggers and renewed selling by FIIs pose short-term challenges to the market. "It is important to appreciate the fact that the biggest challenge to the market is the poor earnings growth, and this is the fundamental factor behind FII selling," he added. Early trade data showed that Bajaj Finance led the gainers with a rise of 1.34%, followed by Asian Paints up 1.32%, NTPC gaining 1.10%, Bajaj Finserv also up 1.10%, and Power Grid advancing 1.06%. The positive momentum in these stocks helped the benchmark index start the session on a firm note. However, a few major names dragged the index down in early trade. Tech Mahindra was the biggest loser, slipping 1.41%, followed by Axis Bank, which fell 0.88%. Infosys declined 0.63%, Titan dropped 0.27%, and Kotak Mahindra Bank edged down 0.08%. Despite these early losses, most of the market sentiment remained positive in the opening minutes of trade. "The Q2 results are unlikely to change the sentiments since the postponement of buying following the GST cuts, impacted corporate sales in September. But, post September the story is different. Automobiles and white goods are witnessing brisk sales and in the low-interest regime, with more rate cuts to come, this demand will sustain," said Vijaykumar.

"These positives will be reflected not in the ongoing Q2 results season but in the Q3 results. The market will soon start discounting that, and that is when a healthy market rally will begin and sustain," he added.

## Pakistan, IMF reach preliminary deal to release \$1.2 billion from bailout package

ISLAMABAD.(Agency)

Pakistan and the International Monetary Fund have reached a staff-level agreement for the release of \$1.2 billion from the bailout package approved last year. The \$7 billion bailout approved by the IMF in July 2024 aimed to keep Pakistan from defaulting on its debt repayments. The agreement following several days of talks in Islamabad was reported by state media Wednesday and the IMF confirmed it in an overnight statement. The IMF said Pakistan's economic program is helping entrench macroeconomic stability and rebuild market confidence. The development comes weeks after Pakistan urged the IMF to consider concessions in light of devastating floods that killed more than 1,000 people and affected some 7 million in recent months. The IMF said the recent floods highlight Pakistan's vulnerability to natural disasters and climate-related risks and stressed the continuing need to build climate resilience. The fund also expressed sympathy for those affected by the disaster.

## IBM, Airtel unveil cloud platform to power India's digital economy

MUMBAI.(Agency)

Bharti Airtel has partnered with IBM to launch a cloud solution designed to meet the country's growing demand for secure, compliant data infrastructure. The partnership marks a major step in India's efforts to localise sensitive data, enhance digital trust, and enable industries to harness AI and hybrid cloud technologies while maintaining regulatory control. The new platform, to be hosted on Airtel's data centres across India, will use IBM Cloud for Telecommunications and IBM Cloud Satellite technologies to ensure that customer data remains within the country. It will enable government departments, public sector undertakings (PSUs), and regulated industries such as banking, healthcare, and manufacturing to store, process, and manage data in compliance with Indian laws — particularly the Digital Personal Data Protection Act (DPDP) and sectoral data localisation norms.

"Enterprises and governments today need cloud infrastructure that not only delivers scale and innovation, but also meets the highest standards of data privacy and security," said Sandip Patel, Managing Director, IBM India & South Asia. "Our partnership with Airtel brings together IBM's global expertise in hybrid cloud and Airtel's deep network and data centre capabilities to offer a truly trusted digital foundation for India." Sharat Sinha, CEO of Airtel Business, added that the solution is built to serve as a "secure cloud for India's mission-critical workloads." "With data now being the most strategic asset, the cloud platform will help Indian enterprises and the government accelerate digital transformation with full control and transparency," he said.

A growing enterprise shift

IBM and Airtel's tie-up also reflects a wider trend among Indian enterprises toward hybrid cloud deployments. Many companies are rethinking pure public cloud strategies due to concerns over rising costs, vendor lock-in, and data portability.

This initiative is expected to integrate with IBM's AI and quantum computing capabilities, allowing enterprises to securely deploy next-generation applications, including those requiring high-performance computing or confidential data analytics. "With this, we are not just building cloud infrastructure — we're laying the digital foundation for India's next decade of innovation," said Patel.

# Sugar sector urges government to push ethanol blending beyond 20%: Report

**Ethanol producers have collectively offered 17,760 million litres for the ethanol supply year 2025–26 (ESY), which far exceeds the oil marketing companies' (OMCs) annual requirement of around 10,500 million litres.**

New Delhi.(Agency)

India's sugar industry is now seeking a higher ethanol blending target with petrol, urging the government to set a clear roadmap to increase blending levels to 27% (E27) once the country achieves the 20% (E20) milestone, reported Financial Express (FE). The proposal aims to ensure that the industry's expanding ethanol production capacity does not remain underutilised. Deepak Ballani, Director General of the Indian Sugar and

Bioenergy Manufacturers Association (ISMA), told FE, "With over Rs 40,000 crore invested and an annual production capacity of more than 9,000 million litres from sugarcane, we are fully equipped to support blending beyond E20, up to E27 and even higher." He added that a well-defined national ethanol mobility roadmap would help maintain momentum in India's biofuel programme while ensuring better use of infrastructure, stable income for sugarcane farmers, and stronger support for rural industries. As reported by FE, ethanol producers have collectively offered 17,760 million litres for the ethanol supply year 2025–26 (ESY), which far exceeds the oil marketing companies' (OMCs) annual requirement of around 10,500 million litres. Out of this, sugarcane-based producers account for nearly 4,710 million litres, while 13,040 million litres come from grain-based units. Ballani cautioned that without a roadmap beyond

E20, large capacities could lie idle, leading to wasted investments, lower mill revenues, and slower innovation in the biofuel space.



The FE report further noted that grain-based ethanol producers—who use rice and maize—have also called for an increase in blending targets and a temporary freeze on new investments. "Units operating at 50% of their capacities would become unviable, as we do not produce any other products unlike the sugar industry," said Chandra Kumar Jain, President of the Grain Ethanol Manufacturers

Association, as quoted by FE. Currently, India's ethanol manufacturing capacity stands at around 17,000 million litres. Of the 400 units across the country, roughly 250 are grain-based, while the rest depend on sugarcane. The OMCs currently buy about 11,000–12,000 million litres of ethanol annually. FE also reported that both ISMA and the Indian Federation of Green Energy (IFGE) have recommended rationalising GST on flex-fuel and hybrid vehicles and offering consumer incentives similar to those under the FAME scheme for electric vehicles. The two organisations argue that such incentives would help sustain the momentum of India's ethanol expansion and encourage cleaner mobility options. They have also asked for a time-bound roadmap covering blending targets, vehicle adaptation standards, and diversification into advanced biofuels such as 2G and 3G ethanol, sustainable aviation fuel, and green chemicals.

## Gold nears Rs 1.3 lakh. Is it wise to buy before Dhanteras



New Delhi.(Agency)

Gold prices in India are approaching record levels just as the festive buying season begins. With Dhanteras around the corner, domestic bullion rates have surged in line with the global rally. Gold prices in India are closing in on the Rs 1.3 lakh mark for 24-carat gold. According to data from Goodreturns, all categories witnessed an increase on Wednesday. As of 15 October 2025, 24K gold is priced at Rs 1,28,360 per 10 grams, 22K is at Rs 1,17,660, and 18K stands at Rs 96,270.

**GLOBAL RALLY FUELS LOCAL SURGE**

Gold and other precious metals have surged between 58% and 80% this

year, placing them among the strongest performers in the commodities market. This sharp rise has been fuelled by sustained central bank buying, increased investments in gold-backed ETFs, and a series of rate cuts by the US Federal Reserve. Safe-haven demand has also strengthened amid persistent uncertainty. Investors are reacting to renewed US-China trade tensions, pressure on the Fed, and the partial shutdown of the US government. Many are also turning to gold as a hedge against ballooning government debt — often referred to as the "debasement trade." Rahul Kalantri, VP Commodities at Mehta Equities Ltd, said market anxiety remains a strong driver.

"Gold and silver extended their bullish streak in a highly volatile session as investors flocked to safe-haven assets. Escalating US-China trade tensions, including threats of retaliation on soybean imports, contributed to the cautious mood," he said. He added that the US situation continues to weigh on sentiment. "The ongoing government shutdown has dampened the economic outlook. Additionally, Fed Chair Jerome Powell flagged risks from slowing hiring, hinting at the possibility of more rate cuts this year. These factors together supported gold's momentum, as markets priced in greater chances of monetary easing in the US."

**SHOULD INVESTORS BUY AHEAD OF DIWALI?**

Addressing whether retail buyers should enter now or wait for a dip, Suvankar Sen, MD and CEO of Senco Gold and Diamonds, said intent matters. "For purchases tied to weddings, Dhanteras, or gifting, cultural and emotional value usually outweighs short-term price concerns. Customers still want to mark special occasions, even when rates are high." For investment buyers, he suggested a staggered approach.

"Some may prefer to buy in phases rather than wait for a dip, especially given the unpredictability of macroeconomic signals. This strategy helps reduce timing risk while still maintaining exposure."

## Diwali Picks 2025: How can you build your portfolio this festive season

New Delhi.(Agency)

As Diwali 2025 approaches, the mood on Dalal Street isn't euphoric, but there is fresh optimism. After months of sharp moves and short-lived rallies, the markets have settled into a sideways rhythm. The Nifty has been hovering near 24,000, pausing after a strong bounce from its summer lows.

The market might look like it's stalling, but what's really happening is a deep breath before the next sprint. Choice Broking's Samvat report calls this phase "a healthy pause in an ongoing uptrend," noting that the Nifty has built a strong floor near 24,000. In other words: the rally isn't over, it's just catching its breath. Choice Broking believes investors should use this phase to build, not wait. "For long-term investors, gradual accumulation now can create a solid foundation for the

next leg," its report notes, pegging Nifty targets of 26,500–28,000 by Diwali 2026.

**BANKS LEAD THE CHARGE**

Bank Nifty has quietly been leading the charge. Currently near 56,500, the index has broken past its earlier resistance of 54,000 and successfully retested it as support, which is a technically strong sign. It's trading above its key 20-, 50- and 200-week moving averages, and the pattern of higher highs and higher lows on the weekly charts suggests that the uptrend is intact. Analysts see strong buying interest emerging between 53,500 and 54,000—the zone to watch for those looking to add exposure to financials.

As long as the index holds above this band, the broader view stays bullish. The medium-term targets? Around 60,000–62,500 by next Diwali.

**DIWALI PICKS FOR INVESTORS**

Among individual stocks, Choice Broking highlights several names that have shown technical strength and are well-positioned for the next leg of the rally. Federal Bank, trading around Rs 213, has built a firm base and is inching toward a breakout above Rs 220. A move past that could take it to Rs 245–255, while dips toward Rs 207 may offer entry opportunities. Cipla, at Rs 1,545, is forming an ascending triangle pattern—a sign of a potential breakout above Rs 1,580, with upside targets near Rs 1,770–1,850. In the defence space, Bharat Dynamics Ltd (BDL) continues to look strong at around Rs 1,485, supported by robust structure and healthy volume trends. The stock could move toward Rs 1,700–1,785 over the coming months.

## Is Goldman Sachs planning to cut jobs? Check here

New Delhi.(Agency)

Goldman Sachs is preparing for another round of job cuts in 2025 as it reshapes its business around artificial intelligence. The move is part of its new "OneGS 3.0" strategy, which aims to cut costs, boost productivity and shift focus to technology-led operations, according to Bloomberg.

**FRESH LAYOFFS ON THE WAY**

In a memo shared with staff and reported by Bloomberg, the bank said it would carry out a "limited reduction in roles across the firm" and restrict headcount growth for the rest of the year. Employees were told to expect the next phase of cuts in 2025. "We model LG India to report revenue/PAT CAGR of 9.3%/7.9% over FY25–28E. Goldman Sachs had about 48,300 employees at the end of September—around 1,800 more than the same time last year. Despite the new job cuts, the bank still expects to finish the year with a net increase in staff, as hiring continues in select growth areas.

**ONEGS 3.0: AI AT THE CORE**

The company's new strategy, OneGS 3.0, aims to



integrate AI across several parts of the business. Tasks such as client onboarding, lending, regulatory reporting and vendor management are expected to be streamlined using new technology. Chief Executive Officer David Solomon, along with President John Waldron and Chief Financial Officer Denis Coleman, said in the memo that the bank is only at the "early innings" of adopting AI. However, they stressed that the technology will change how the firm operates and how work is balanced between people and machines. They also said that achieving speed and agility will be essential as AI tools become more central to the business.

**PREVIOUS JOB CUTS AND SHIFTING ROLES**

Goldman Sachs has already gone through several rounds of layoffs over the past year. Earlier in 2024, the bank cut around 700 roles as part of its annual workforce review.

# Expecting your entire CTC as salary Here's the reality check

**Many first-time earners walk into their jobs assuming the number on their offer letter will land in their bank account. But when the first payslip arrives, reality hits hard. The gap between CTC and take-**

New Delhi.(Agency)

Many fresh graduates are discovering a harsh financial truth in their first month of employment — the salary they expect is not always the salary they receive. An example, shared by CA Abhishek Walia, highlights just how common this problem is among young professionals.

**THE SALARY SHOCK**

Walia recalled a 24-year-old client who approached him barely a month after starting her first job. She looked puzzled and said, "I thought I'd get Rs 60,000, but only Rs 48,500 came in." Classic CTC confusion," he said. Like many new employees, she assumed that the package mentioned in her offer letter would reflect her actual take-home salary. Her offer letter quoted a Rs 60,000 monthly



package, but she hadn't realised that the figure included deductions like provident fund, gratuity and taxes. The misunderstanding derailed her early financial plans—her rent budget didn't work out, and the SIP she wanted to start was put on hold.

**BREAKING DOWN THE NUMBERS**

To help her understand where things went wrong, Walia broke it down in simple terms. "CTC = Company Cost, not Cash

to Credit. In-hand is roughly 70 to 90% of your CTC after taxes and deductions," he said. This clarity was the first step in fixing the damage caused by a misunderstanding. Once she understood the difference between CTC and take-home salary, her financial planning could begin properly. Walia helped her start a Rs 3,000 SIP, open a PPF account and set a target of building a Rs 10,000 emergency fund. These basic steps gave her a sense of

control and direction, something she had lost after her first payslip arrived.

**WHY SALARY AWARENESS MATTERS**

Walia believes this issue is more common than many realise and can have lasting effects if not addressed early. "It's simple, but eye-opening: you can't manage money you don't understand. Before you invest, learn to read your payslip," he said. Many first-time earners enter the workforce without knowing how deductions work, which leaves them unprepared to manage their income.

**FINANCIAL LITERACY IS NO LONGER OPTIONAL**

With more young professionals entering the job market each year, understanding payslips, tax breaks and salary structures is becoming essential. As Walia pointed out, "Remember, financial literacy isn't optional anymore. It's your first line of defence against regret." His advice serves as a timely reminder: knowing your salary on paper is not the same as knowing what lands in your bank account — and the difference can define your financial stability from day one.

# Sex abuse, gangsters, bribes: Twin cop suicides expose rot in Haryana Police

**Haryana Cop Suicide: The saga, which started with the suicide of senior IPS officer Y Puran Kumar, took a new twist this week after an assistant sub-inspector (ASI) allegedly shot himself and blamed the former of corruption.**

**Agency New Delhi.**

The mystery surrounding the shocking suicides of two senior Haryana police officers is getting murkier by the day amid allegations of caste discrimination, corruption, and extortion within the state police force. Allegations of police-gangster links have also emerged, throwing the Haryana Police into a credibility crisis. The saga, which started with the suicide of senior IPS officer Y Puran Kumar, who accused his seniors of harassment and caste discrimination, took a new twist this week after an assistant sub-inspector (ASI), Sandeep Lathar, allegedly shot himself and blamed the former of corruption. Amid mounting pressure, the BJP government sent Haryana DGP Shatruej Kapur on leave and replaced Rohtak's superintendent of police, Narendra Bijraniya. They were among the eight senior IPS officers named by Puran Kumar in his suicide note.

Congress and the opposition alleging that Puran Kumar, a Dalit, was forced to take the extreme step due to systematic discrimination. With fresh details emerging each day, here is a



recap of what has happened so far. To understand the sequence of events, we need to go back to September 29, eight days before Puran Kumar allegedly shot himself dead. **SEPTEMBER 29: THE TRANSFER** On September 29, Puran Kumar, a 2001-batch IPS officer, was transferred from the post of IG

(Rohtak range) to Sunaria Police Training College. The transfer, which allegedly came without prior intimation, deeply disturbed the 52-year-old officer. He gave up the post on September 30, and went on leave for a week.

**OCTOBER 1: PSO'S DETENTION**

On October 1, while he was travelling from Rohtak to Chandigarh with his Personal Security Officer (PSO) Sushil Kumar, Puran Kumar's car was intercepted by a Rohtak police team, which included ASI Sandeep Lathar.

Puran Kumar's security officer was detained without any FIR or warrant being shown. When Kumar objected, the police allegedly threatened him, saying, "Next, it will be your turn". Before being taken into custody, PSO Sushil Kumar left his service revolver in the car - the gun that Puran Kumar later used to shoot himself, sources said.

**OCTOBER 1-5: INTERROGATION**

Sources said PSO Sushil Kumar was interrogated for five days in illegal custody, as no formal case was registered at that time.

## NCRTC advances Delhi-Gurugram-SNB RRTS corridor, floats consultancy tender



**Agency New Delhi.**

The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) has advanced plans for the Delhi-Gurugram-SNB section of the Delhi-Alwar Regional Rapid Transit System (RRTS), a key corridor under Phase I of the 164-km Delhi-Alwar project. A tender has been floated to appoint a general consultant responsible for project management, design reviews, quality assurance, and inter-agency coordination to ensure timely execution.

The consultancy bid requires a security deposit of Rs 4.64 crore, with a pre-bid meeting scheduled for October 24. The selected consultant will serve a 60-month term from the commencement date.

The corridor will link Sarai Kale Khan in Delhi to Alwar, passing through Munirka, Aerocity, Gurugram, Rewari, and Sotanala. It will feature 22 stations—17 elevated and five underground—offering a fast, reliable travel option while easing congestion and pollution in the NCR. Prioritised under the PM Gati Shakti Master Plan in 2023, the RRTS aims to strengthen regional connectivity.

## Delhi to launch driver-owned cooperative ride-hailing service

**Agency New Delhi.**

In a bid to make urban commuting fairer for both passengers and drivers, the Delhi government is planning to launch a cooperative ride-hailing service within the city.

The move, announced by Social Welfare and Cooperation Minister Ravindra Indraj, is aimed at providing affordable travel options without surge pricing, while allowing drivers to retain their full earnings without any commission cuts.

Indraj said the proposed initiative is part of the government's larger effort to "revitalise the cooperative movement in the city with new direction and energy." He added that by placing control directly in the hands of drivers, the service would not only ensure transparency in fares but also foster a sense of ownership among those behind the wheel. Unlike existing corporate-run cab aggregators, the new platform will be fully managed and owned by its drivers through a cooperative structure. The service will function via a dedicated mobile application that directly connects passengers with drivers, cutting out the middleman.

According to officials, the cooperative model will bring together two-wheelers, taxis, auto-rickshaws, and four-wheelers under one unified system. Drivers, as members of the cooperative, will share profits equitably and participate in key management decisions.

The government believes this model could create a more sustainable and inclusive urban transport network. "Passengers can benefit from this cooperative-run ride-hailing service in Delhi through reliable service, transparent fares, and no unexpected price surges. It will uplift drivers by improving their income, working conditions, and overall quality of life. This approach aims for a win-win scenario where drivers enjoy social security benefits and fair profit-sharing, while commuters get affordable rides," an official said.

## Gang rape FIR filed in sex assault case at Delhi's South Asian University

**Agency New Delhi.**

In a horrifying incident, an 18-year-old B.Tech student of the South Asian University (SAU) was allegedly sexually assaulted by four men, including a security guard, on the campus. The survivor stated in her complaint that an attempt was made to strip her and force a pill down her throat. The incident took place on Sunday. The police registered an FIR on her complaint on Tuesday under Sections 70 (gang rape) and 62 (attempt to commit an offence punishable with life imprisonment), among others, of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The survivor's statement has been recorded in the district magistrate's court.

She stated in her complaint that for the last two to three days, she had been receiving sexually explicit and threatening emails from an account, identified as that of one Aryan Yash, and messages on WhatsApp and Telegram apps.

In these emails and messages, the sender asked her to meet the sender at various locations on the campus. The sender also sent her morphed obscene pictures in these messages. The survivor wrote in the complaint, "I was going towards C-Block [at the campus] from the backside of the hostel. I saw a crowd over there and avoided going towards that area. I thought that he could be one of them and went towards the backside of the building. Then I went straight towards the convocation center."

She said that a guard enquired from her what she was doing at that secluded spot. He later called a middle-aged man and two other persons there. While she was leaving from there, one of them allegedly tried to remove her jacket, she said, while another person put his finger in her eyes. She was pushed, following which she fell on the ground. One of them came close to her and said, "I will kill your child." Later, she said, one of them tried to push a pill under her tongue, but she spat it out. He tried to kiss her and wanted to bite on her neck. They fled from the spot when they noticed someone coming there, the FIR said. A senior police officer said that the Maidan Garhi police station received a PCR call on Monday at around 3 pm regarding sexual assault of a student at South Asian University.

## New office-bearers for DUTA; opposition groups condemn remarks by VC

**Agency New Delhi.**

The Delhi University Teachers' Association (DUTA), on Tuesday, elected its new office-bearers and five co-opted members in a meeting of the newly elected executive held nearly 40 days after the main DUTA polls on September 4.

The panel backed by the National Democratic Teachers' Front (NDTF), AADTA, and Social Democratic Teachers Front (SDTF) swept all posts, securing 10 votes each. Bhupendra Singh (SDTF) was elected vice president, Bimalendu Tirthankar (AADTA) as secretary, Sanjay Kumar (NDTF) as joint secretary, and Akansha Khurana (NDTF) as treasurer.

The co-opted members include Aparna Nautiyal, Ram Babu Pachwaria, Sandeep Singh Sokhi and Suman Das (all from NDTF), and Priyam Barooah (AADTA). The opposition panel—comprising DTF, INTEC (I), INTEC, and CTF—secured six votes per post. It fielded Chhotu Ram Meena (INTEC I) for vice president, V S Dixit (DTF) for secretary, Dinesh Kataria (DTF) for joint secretary and Yasha Yadav (DTF) for treasurer.

The co-opted nominees were from DTF and CTF. In a joint statement, DTF and INTEC (I) said that their alliance was meant to register "a statement of resistance against the onslaught of a repressive state machinery and its local agents" following two controversial incidents—the vice-chancellor's remark labelling dissenting teachers as "Urban Naxals" and DUTA president V S Negi's statement equating Ambedkarism with "Manuvad".

The statement accused AADTA and SDTF of "betraying teachers' mandate" by aligning with NDTF despite earlier promises to uphold social justice. The opposition vowed to continue its struggle to defend constitutional values, oppose the non-filling of sanctioned posts, seek regularisation of ad-hoc teachers and resist the NEP-imposed UGCF structure.

## Delhi announces full waiver on late payment surcharges for water bills

**Agency New Delhi.**

In a significant move aimed at providing relief to city residents, Chief Minister Rekha Gupta has announced a 100% waiver on late payment surcharges (LPS) for water bills. The waiver, which covers approximately Rs 11,000 crore in overdue surcharges, applies to domestic consumers who clear their pending water bills by January 31, 2026. The Late Payment Surcharge Waiver Scheme offers full relief from late payment charges if outstanding water dues are paid by the deadline.

Payments can be made either in lump sum or in installments, but the waiver will only apply once the principal amount has been fully settled. The government also announced a 70% waiver on late payment charges for payments made between 1 February and 31 March 2026.

Chief Minister Gupta described the initiative as a "Diwali gift" for the people of Delhi, stressing that the scheme is designed to encourage timely payments while also easing the financial burden on residents.



Water Minister Parvesh Sahib Singh reinforced the government's intent to improve the efficiency of the Delhi Jal Board, adding that the waiver will be a one-time opportunity for consumers to clear their dues without additional

penalties. The Delhi government is also launching the Unauthorised Water and Sewer Connection Regularisation Scheme, which aims to address the issue of illegal connections.

This scheme offers substantial reductions in penalties for consumers with unauthorised water or sewer connections. For domestic connections, the penalty has been reduced from Rs 25,000 to just Rs 1,000, while non-domestic connections will face a reduced penalty of Rs 5,000, down from Rs 61,000. However, the waiver applies only to penalties, and regular water and sewer charges, along with infrastructure fees, must still be paid.

The regularisation scheme will remain in effect until January 31 2026, after which any unregularised connections will be disconnected, the CM said.

## GRAP Stage I curbs imposed in Delhi as AQI falls to 'poor' category

**Agency New Delhi.**

The Commission for Air Quality Management (CAQM) on Tuesday imposed Stage I measures of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR after the city's air quality index hit 211 on Tuesday, pushing the capital into the "poor" category and prompting authorities to step up curbs ahead of Diwali.

The sub-committee on GRAP, which reviewed real-time data from the Central Pollution Control Board (CPCB) and forecasts from the India Meteorological Department and the Indian Institute of Tropical Meteorology, said stagnant weather would likely keep pollution levels elevated for the coming days and



authorised immediate implementation of Stage-I actions.

Under the order, local administrations, municipal bodies and pollution control boards across Delhi and neighbouring districts in Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and Punjab have been directed to implement dust-control at construction and demolition sites,

with projects larger than 500 square metres required to operate an approved dust management plan and water-sprinkling mandated at open sites. Open burning of garbage, leaves and other waste is banned, and roadside food stalls and commercial kitchens have been instructed to switch from coal and firewood to electricity, gas or other clean fuels.

Diesel generators are to be restricted to essential or emergency use only, and visibly polluting vehicles may be fined or impounded.

Traffic measures include enhanced deployment of traffic police at key intersections and an appeal to motorists to switch off engines at signals and avoid idling.

# Defiant India keeps Russia its top oil source. But here's the real story

**Overall, India has remained defiant in its energy choices, keeping Russia as its top oil supplier despite mounting US tariffs and diplomatic pressure. While state refiners have cut back, private giants like Reliance Industries and Nayara Energy have significantly increased Russian crude imports.**

**Agency New Delhi.**

Despite repeated and relentless tariff tantrums, arm-twisting, trash-talk, and sanction sabres by US President Donald Trump and his aides, India has kept Russia its top oil supplier in September, sourcing 34% of its crude imports from Moscow. However, there was a 10% drop in oil imports from Russia since January. The latest figures from the Belgian commodities and shipping market tracker Kpler come amid Trump's imposition of a 50% tariff on imports from India this August. This included an additional 25% penalty on purchases of Russian oil. Washington has insisted that New Delhi halt its crude imports from Moscow as a precondition for negotiating a favourable trade deal. With imports averaging 1.6 million barrels per day (bpd) out of total crude

arrivals exceeding 4.5 million bpd, Indian refiners have visibly shrugged off Washington's pressure, and prioritised discounted Urals crude that offered \$2-3 per barrel savings against Brent benchmarks.

However, there is a bigger story here. While state-run refiners have cut imports from Russia by 45%, sourcing of crude from Moscow by private operators reached its highest point in September.

Historically, Russia wasn't India's primary source of crude oil. After Russia's invasion of Ukraine in February 2022, India ramped up its oil imports from a negligible 0.2% of total imports to 35-40%, saving an estimated \$17 billion through discounted purchases.

**1. WHY TRUMP WANTS INDIA TO STOP OIL PURCHASE FROM RUSSIA?**

The sanction saga over Russian crude



began in earnest this summer, as Trump, in his second term, ramped up his crusade against Moscow's Ukraine invasion. This was because Trump was

eyeing the Nobel Peace Prize as a "peace president". On August 1, he slapped a 25% "reciprocal" tariff on Indian exports like textiles, gems, and pharmaceuticals (valued at \$87 billion annually) citing longstanding trade imbalances.

But the real sting came days later. Through an executive order, Trump doubled duties on Indian goods to 50% effective August 27. By doing this, he explicitly punished New Delhi for "directly or indirectly importing Russian Federation oil" that he said was "funding Putin's war machine". White House trade advisor Peter Navarro branded India a "profiteer", while Treasury Secretary Scott Bessent accused it of exploiting discounted Russian barrels.

## NEWS BOX

## Indian-origin expert Ashley Tellis arrested for unlawful retention of classified US documents: Report

World (Agency)

Ashley Tellis, a leading U.S.-India relations expert who has advised successive U.S. administrations, was arrested over the weekend and charged with unlawful retention of national defense information, including more than a thousand pages marked top secret and secret, news agency Reuters reported, citing court documents. Tellis, 64, who served on the National Security Council under former President George W. Bush and is listed in an FBI affidavit as an unpaid adviser to the State Department and a Pentagon contractor, is also a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, a Washington-based think tank, Reuters added. Tellis was born in India and is now a naturalised US citizen. According to the FBI affidavit seen by Reuters, in September and October this year, Tellis accessed and printed classified documents, including materials on military aircraft capabilities, at Defense and State Department buildings and carried them away in a leather briefcase. A search of his Vienna, Virginia, residence on Saturday reportedly uncovered over a thousand pages of classified material. The affidavit also notes, Reuters reported, that Tellis met Chinese government officials on multiple occasions in recent years, including a dinner in Fairfax, Virginia, on September 15, where he reportedly arrived with a manila envelope that was not present when he left. Tellis held a Top Secret clearance with access to Sensitive Compartmented Information due to his employment with the State Department and Pentagon.

A Justice Department statement cited by Reuters said that if convicted, Tellis could face up to 10 years in prison and a fine of USD 250,000. Lindsey Halligan, U.S. attorney for the Eastern District of Virginia, told Reuters: "We are fully focused on protecting the American people from all threats, foreign and domestic. The charges as alleged in this case represent a grave risk to the safety and security of our citizens." U.S. officials have consistently emphasised the prosecution of individuals who mishandle classified information, Reuters noted.

## Britain Is Ill-Prepared For Extreme Weather, Warn Climate Advisers

London (Agency)

Britain must urgently prepare for global warming of at least 2 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2050, its climate advisers said on Wednesday, warning the country is ill-prepared for extreme weather that is already occurring. Britain this year experienced its warmest summer since records began, which impacted health, agriculture and infrastructure with droughts declared in several regions. "It is clear we are not yet adapted for the changes in weather and climate that we are living with today, let alone those that are expected over coming decades," the Climate Change Committee wrote in a letter to the government in response to a request for advice from an environment minister.

READ: Earth May Have Crossed Its First Climate Tipping Point as Coral Reefs Collapse

The CCC outlined six critical areas: public health, food security, infrastructure resilience, protection of cities and towns from extreme weather disruption, maintenance of public services and climate-resilient economic growth. Most governments promised under the 2015 Paris Agreement to try to prevent the average global temperature rise from exceeding 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. But scientists have been surprised by how quickly changes are unfolding, with average global temperatures already having warmed by 1.3-1.4 degrees Celsius above the pre-industrial average, according to data from UN and EU science agencies.

## India Elected To UN Human Rights Council For 7th Time

New York (Agency)

India has been elected to the United Nations Human Rights Council (UNHRC) for the 2026-28 term, marking the country's seventh stint on the Geneva-based rights body. Announcing the results of the election held on Tuesday, the UNHRC in a social media post said India's three-year term will begin on January 1, 2026. India's Permanent Representative to the UN, Parvathaneni Harish, in a social media post, thanked all delegations for their overwhelming support. "India was elected to the Human Rights Council for the term 2026-28 for the seventh time today," he said. This election, the diplomat said, reflects India's unwavering commitment to human rights and fundamental freedoms. "We look forward to serve this objective during our tenure," he said.

The UN Human Rights Council consists of 47 member states elected by the UN General Assembly for three-year terms under equitable geographic distribution rules. Council seats are allocated to the five regional groups as follows: African States, 13 seats; Asia-Pacific States, 13 seats; Eastern European States, 6 seats; Latin American and Caribbean States, 8 seats; and Western European and other States, 7 seats. India, which last served on the UNHRC in 2024 following two consecutive terms, took a gap this year before seeking election for the 2026-28 term in compliance with rules that bar a third straight tenure.

India has been a member of the Council continuously since its creation in 2006, except for three mandatory breaks in 2011, 2018, and 2025. In the first Council election in 2006, India was elected with the highest number of votes, securing 173 of 190 votes. Since then, India has had six terms, in 2006-2007, 2008-2010, 2012-2014, 2015-2017, 2019-2021 and 2022-2024.

# Russia makes more precise drones and is using them to attack Ukraine's vital rail network

**Russia has stepped up railway attacks over the past three months, seeking to sow unrest in Ukrainian regions it borders by depriving people there of rail connections.**

KYIV. (Agency)

When Russian drones smashed into the Shostka train station in northeastern Ukraine earlier this month, they killed a 71-year-old man, injured at least eight people and left train cars buckled by fire and riddled with shrapnel holes. It was one of the latest examples of what Ukrainian officials say has been a surge since mid-summer in attacks on railways, a critical artery for commercial and military logistics. They are part of Russia's broader targeting of infrastructure that now is being carried out with greater precision thanks to advances in long-range drone technology that include onboard video feed.

In the attack in Shostka, less than 70

kilometers (43 miles) from the Russian border, two explosives-laden drones struck two commuter trains in quick succession.

Russia has stepped up railway attacks over the past three months, seeking to sow unrest in Ukrainian regions it borders by depriving people there of rail connections, Oleksandr Pertsovskiy, the CEO of the Ukrainian state railway, told The Associated Press. "What happens is not just about the quantity, it's also the approach of enemy forces. Now, as they have very precise Shahed drones, they are targeting individual locomotives," Pertsovskiy said. Attacks have picked up pace

Ukrainian railway managers have prided themselves on speedy repairs and their ability — so far — to keep the trains running despite repeated strikes, but officials and analysts warn that advances in Russian drone capabilities and the growing tempo of attacks pose a serious threat.

Since the start of Russia's full-scale invasion in early 2022, railway officials have publicly reported about roughly one attack on railways per week. Since mid-summer of this year, that rate has more than doubled

to about two or three per week, according to an AP review of public reports.

However, what is publicly reported is only a small fraction of the overall number of attacks on all rail-related infrastructure, which could include damage to power lines,



electrical substation, rail tracks, train stations and other structures. Oleksii Kuleba, a deputy prime minister in charge of restoration and development, said there have been 300 attacks on railway infrastructure since August alone — which would represent about 10 attacks per week. Ukraine's rail network carries more than 63% of the country's freight and 37% of

passenger traffic, according to the State Statistics Service. It is also essential for moving grain and metal industry exports to seaports and borders, and for transporting military aid from allied nations. Russia developing new drone capabilities. Russian forces have added a key upgrade to their drone fleet since the summer, according to Serhii Beskrestnov, a Ukrainian military and drone expert whose team studies intercepted Russian drones. Cameras and radio modems, which send and receive data wirelessly, have been fitted to various types of long-range strike drones. That allows operators to adjust a drone's flight path in real time, sharply increasing precision compared to preprogrammed models. Beskrestnov said locomotives are particularly vulnerable to the new technology, because they are relatively slow and follow predictable routes. "If the Russians keep hitting diesel and electric locomotives, the time will come very soon when the track will still be intact — but we'll have nothing left to run on it," he said. The modified drones can fly up to 200 kilometers.

## Trump threatens to yank World Cup games from Boston though it's up to FIFA to choose sites

WASHINGTON. (Agency)

US President Donald Trump on Tuesday threatened to relocate World Cup matches set to be played next year in suburban Boston, after suggesting that parts of the city had been "taken over" by unrest.

Foxborough, Massachusetts, home to the NFL's New England Patriots and about 30 miles from Boston, is set to stage matches as the US cohosts the 2026 World Cup with Mexico and Canada. Trump was asked about Boston's mayor, Michelle Wu, a Democrat whom he called "intelligent" but "radical left." "We could take them away," Trump said of the World Cup games. "I love the people of Boston and I know the games are sold out. But your mayor is not good." He suggested "they're taking over parts of Boston" without offering details, but added "we could get them back in about two seconds." The Trump administration has already deployed National Guard troops to Washington and Memphis, and efforts to do so in Chicago and Portland,

Oregon, have sparked legal fights. Wu's office did not react directly to Trump's threat, issuing a statement that read, "Boston is honored and excited to host World Cup matches, and we look forward to welcoming fans from around the world to our



beautiful city, the cradle of liberty and city of champions." Trump's comments came during his meeting with Argentina President Javier Milei and it wasn't immediately clear what he was referring to by parts of Boston having been seized. Earlier this month, however, there were multiple arrests in connection with a pro-Palestinian protest that turned violent on Boston

Common. Four police officers were injured. Trump has previously suggested he could declare cities "not safe" for the 104-game soccer tournament and alter a detailed hosting plan that FIFA confirmed in 2022. It includes games at NFL stadiums near New York, Los Angeles and San Francisco. World Cup host sites aren't up to Trump. The 11 US cities — plus three in Mexico and two in Canada — are contracted with FIFA, which would face significant logistical and legal issues to make changes in the eight months before the June 11 kickoff. "It's FIFA's tournament, FIFA's jurisdiction, FIFA makes those decisions," the soccer body's vice president Victor Montagliani said earlier this month at a sports business conference in London.

Trump nonetheless said, "If somebody is doing a bad job, and if I feel there's unsafe conditions, I would call Gianni — the head of FIFA who's phenomenal — and I would say, 'Let's move into another location' and they would do that."

## US Supreme Court to hear key minority voting rights case that could reshape control of Congress

According to voting advocacy groups, a Supreme Court ruling striking down Voting Rights Act protections for minorities could lead to Republicans picking up an additional 19 seats in the House.

WASHINGTON. (Agency)

The US Supreme Court hears a case involving Black voters on Wednesday that could have lasting repercussions on whether Democrats or Republicans control the House of Representatives.

The case touching on the thorny issues of race and politics is a challenge to a congressional map adopted by the Louisiana state legislature creating a second Black majority district. The conservative-dominated top court actually heard the case last term, but in an unusual move it decided not to issue a ruling and scheduled it for re-argument during the current session.

African-Americans tend to overwhelmingly vote Democratic and they make up one-third of the population of Louisiana, which has six congressional districts.

Following the 2020 census, Louisiana created a new congressional map that included only one Black majority district instead of the previous two.

The American Civil Liberties Union (ACLU) and others filed suit claiming the new map diluted Black voting power and violated the Voting Rights Act, which was passed during the civil rights movement in 1965 to remedy historic racial discrimination.

The Louisiana legislature released a new map last year with two Black majority districts that was met with the legal challenge from a group of "non African-American" voters. It has now reached the Supreme Court, where conservatives hold a 6-3 majority.

The opponents of the redrawn map argue that using race to design congressional

districts is racial gerrymandering prohibited by the equal protection clause of the 14th Amendment to the US Constitution. "The stakes are incredibly high," said ACLU attorney Sophia Lin Lakin.

"The outcome will not only determine the next steps for Louisiana's congressional map, but may also shape the future of redistricting cases nationwide." Republicans currently hold a slim majority in the House and an increase or decrease in the number of Black majority districts could help tip the balance in the November 2026 midterm elections, when all 435 seats in the chamber will be up for grabs.

'One-party control' According to a report by two voting advocacy groups, Fair Fight Action and Black Voters Matter, a Supreme Court ruling striking down Voting Rights Act protections for minorities could lead to Republicans picking up an additional 19 seats in the House.

## As Israel frees some Gaza medical staff, a prominent hospital chief remains imprisoned

CAIRO. (Agency)

Under Gaza's ceasefire deal, Israel freed dozens of doctors, nurses, paramedics and other medical personnel seized during raids on hospitals. But more than 100 remain in Israeli prisons, including Dr. Hossam Abu Safiyya, a hospital director who became the face of the struggle to keep treating patients under Israeli siege and bombardment.

Despite widespread calls for his release, Abu Safiyya was not among the hundreds of Palestinian detainees and prisoners freed Monday in exchange for 20 hostages held by Hamas. Abu Safiyya, director of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, has been imprisoned without charge by Israel for nearly 10 months.

Health Workers Watch, which documents detentions from Gaza, said 55 medical workers — including 31 doctors and nurses — were on lists of detainees from Gaza being freed Monday, though it could not immediately be confirmed all were released.

The group said at least 115 medical workers remain in custody, as well as the remains of four who died while in Israeli prisons, where rights groups and witnesses have reported frequent abuse. Cheering staff from al-Awda Hospital carried on their shoulders their released director, Ahmed Muhanna, who was held by Israel for about 22 months since being seized in a raid on the facility in northern Gaza in late 2023. "Al-Awda Hospital will be restored, its staff will rebuild it with their own hands. ... I am proud of what we have done and will do," Muhanna told well-wishers, his face visibly gaunter than before his detention, according to video posted on social media. Al-Awda Hospital, damaged during multiple offensives in the largely leveled Jabaliya refugee camp, has been shut down since May, when it was forced to evacuate during Israel's latest offensive. Israel's two-year campaign aiming to destroy Hamas after its Oct. 7, 2023, attack decimated Gaza's health system, forcing most of its hospitals to shut down and heavily damaging many, even as staff struggled to treat waves of wounded from bombardment amid supply shortages.

During the war, Israeli forces raided a number of hospitals and struck others, detaining hundreds of staff. Israel says it targeted hospitals because Hamas was using them for military purposes, a claim Palestinian health officials deny. Abu Safiyya was not known if Abu Safiyya, 52, might still be released. Israeli officials did not immediately respond to requests for comment. His family said on social media there were "no confirmed details about the date of his release," adding that freed detainees described him as "in good health and strong spirits." Working for Hamas. Staff and international aid groups that worked with him deny the claims.

# Pakistan reports new clash with Afghan forces along northwestern border

Tensions have remained high since last week, when the Taliban government accused Pakistan of carrying out airstrikes in Kabul and in an eastern market. Pakistan has not acknowledged those allegations.

PESHAWAR. (Agency)

Clashes erupted Tuesday between Pakistani and Afghan forces in a remote northwestern border region, with state-run media in Pakistan accusing Afghan troops of opening "unprovoked fire" that was repulsed. Pakistani forces responded, damaging Afghan tanks and military posts, according to Pakistan TV and two security officials, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak to the media.

Tahir Ahrar, a deputy police spokesperson in Afghanistan's Khost province, confirmed the clashes but provided no further details. This is the second time this week that the two sides have traded fire along their long border. According to Pakistan's state-run



media, Afghan forces and Pakistani Taliban jointly opened fire at a Pakistani post "without provocation," prompting what the media described as a "strong response" from Pakistani troops in

Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa province.

Security officials said Pakistan's military also destroyed a sprawling training facility of the Pakistani Taliban. There was no immediate comment from Pakistan's military, which has been on high alert since Saturday, when both sides traded fire across multiple border regions, resulting in dozens of casualties on each side.

Although the clashes halted on Sunday after appeals from Saudi Arabia and Qatar, all border crossings between Pakistan and Afghanistan have remained closed.

Over the weekend, Kabul said that it targeted several Pakistani military posts and killed 58 Pakistani soldiers in retaliation for what

it called repeated violations of Afghan territory and airspace. Pakistan's military reported lower figures, saying it lost 23 soldiers and killed more than 200 "Taliban and affiliated terrorists" in retaliatory fire along the frontier. Tensions have remained high since last week, when the Taliban government accused Pakistan of carrying out airstrikes in Kabul and in an eastern market. Pakistan has not acknowledged those allegations.

But Pakistan has previously launched strikes inside Afghanistan, saying it targets hideouts of Tehreek-e-Taliban Pakistan, or TTP, which is separate from but allied to the Afghan Taliban. Pakistan accuses Kabul of harboring the group, which has carried out numerous deadly attacks inside Pakistan. Kabul denies the charge, saying it does not allow its territory to be used against other countries.

## NEWS BOX

## Don't call it a home Test just because the venue is on Indian map: R Ashwin

New Delhi. (Agency)

Just because the Indian team is playing within the boundaries of the Indian map does not necessarily mean they are playing in familiar home conditions. Ravichandran Ashwin has made a striking and somewhat controversial claim following India's Test series against the West Indies. The Indian Test team recently played matches in Ahmedabad and New Delhi against the West Indies and is scheduled to travel to Kolkata and Guwahati for a two-match Test series against South Africa later in November and December. The recently retired spinner expressed his concern that having such a large number of home venues across the country does not always benefit the Indian team, even when they are technically playing at home. Ashwin elaborated that when India plays Test matches at venues where they do not play red-ball cricket regularly, the team is unable to fully capitalise on the home advantage. In his view, familiarity with conditions is critical, and without regular exposure to these venues, the team is left guessing about pitch behaviour and conditions, despite being the home side. The former spinner further added that there are significant challenges involved



in playing across different parts of India, as the country's diverse geography leads to vastly different pitch conditions and playing environments from one region to another.

"In Guwahati, when you play South Africa, maybe India will play well and trouble South Africa. But just because it's a part of the Indian map, it doesn't automatically become a true home game for India. I see it as an away game for India within India. Because we have not played a lot of Test matches at such venues. As the home team, we didn't know what to expect. I am talking from that perspective," Ashwin said on his YouTube channel.

## India's Test Venues

The Tamil Nadu spinner stated that India needs to establish fixed Test centres for hosting international matches, especially against visiting teams, in order to gain maximum home advantage.

## India women's team visits Mahakaleshwar Temple after twin World Cup losses

New Delhi. (Agency)

The Indian women's cricket team visited Ujjain's Mahakaleshwar Temple on October 15, 2025, to seek blessings after suffering back-to-back defeats to South Africa and Australia in the ICC Women's World Cup. The players participated in the early morning Bhama Aarti and spent time offering prayers in the Nandi Hall.

Back-to-back three-wicket defeats to South Africa and Australia in Vizag have put India's World Cup campaign on hold. Led by Harmanpreet Kaur, the hosts sit third on the points table with four points from four matches and a net run rate of 0.682, with three league-phase games still to play. The team now faces mounting pressure to bounce back if they are to keep their semifinal hopes alive. India's chances of reaching the semifinals remain in their own



hands. A clean sweep of the remaining three games would see them finish with 10 points and secure a spot in the top four. Winning two out of three could see them progress depending on net run rate, while losing two would likely end their semifinal hopes.

India began the tournament on a strong note, beating Sri Lanka in Guwahati and Pakistan in Colombo. However, narrow defeats to South Africa and Australia have put additional pressure on the side to recover. Both opponents exposed the weaknesses in India's five-bowler strategy, targeting the inexperienced pacers Kranti Gaud and Amanjot Kaur, while comfortably negotiating the spinners' spells. India will next face England at Indore on Sunday, followed by matches against New Zealand (October 23) and Bangladesh (October 26) at the D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai. A key focus will be the inclusion of a sixth bowling option to strengthen the attack.

## Ronaldo breaks record but Hungary deny Portugal early World Cup 2026 qualification

**Cristiano Ronaldo set a new record for World Cup qualifying goals, but Hungary secured a late 2-2 draw, preventing Portugal from clinching a spot in next summer's tournament with two games remaining.**

New Delh. (Agency)

Cristiano Ronaldo scored twice and set a new World Cup qualifying record, but Portugal were held to a 2-2 draw by Hungary, missing the opportunity to secure early qualification for the 2026 tournament. At 40, Ronaldo has now netted 41 goals in World Cup qualifying, overtaking the previous record of 39 held by former Guatemala striker Carlos Ruiz. Portugal were on the verge of securing their place at next summer's World Cup in Canada, Mexico, and the United States, with England's 5-0 victory over Latvia in Group K meaning only a win would confirm their qualification. However, a dramatic 91st-minute equaliser from Liverpool midfielder Dominik Szoboszlai denied them victory,



leaving Portugal five points clear at the top of Group F with two matches remaining. Their next chance to seal qualification comes on 13 November, when they face the Republic of Ireland in Dublin. Portugal got off to a poor start in Lisbon, falling behind in the eighth minute when Attila Szalai headed in a well-

placed corner from Dominik Szoboszlai after goalkeeper Diogo Costa failed to claim the ball. The hosts responded in the 22nd minute, with Cristiano Ronaldo converting Nelson Semedo's low cross from close range to level the score. That goal marked Ronaldo's 40th in World Cup qualifying, setting a new all-

time record. Ronaldo struck again just before half-time, finishing Nuno Mendes' cross to score the 948th goal of his career and his 143rd international goal, giving Portugal a 2-1 lead. Despite Portugal's dominance in the second half, hitting the post twice within 15 minutes through Ruben Dias and Bruno Fernandes, they could not extend their advantage. Substitutes, including Joo Flix, were denied by outstanding saves from Hungary goalkeeper Balzs Tóth. Szoboszlai's stoppage-time strike ensured Hungary secured a point and kept their hopes of topping the group alive. Hungary remain second in Group F, just one point ahead of the Republic of Ireland, who defeated Armenia 1-0 in Dublin.

Ronaldo's illustrious 22-year international career has seen him help Portugal win the 2016 European Championship and two UEFA Nations League titles. The closest he has come to World Cup glory was in 2006, when Portugal reached the semi-finals, losing to France and then Germany in the third-place play-off. Portugal must now wait until November to try again to secure their spot at the 2026 World Cup, with Ronaldo once more at the heart of their hopes.

## Ranji Trophy: Prithvi Shaw out for duck as Maharashtra suffer horror start vs Kerala

New Delhi. (Agency)

Prithvi Shaw's Ranji Trophy debut for Maharashtra did not go according to plan, as the opener fell for a four-ball duck against Kerala on Wednesday, October 15. Shaw, who had looked impressive in the warm-up game ahead of the tournament, was trapped plumb in front of the stumps by pacer MD Nidheesh. It wasn't just Shaw - three other Maharashtra batters were also dismissed for a duck within the first 20 balls of the match, as Kerala ran riot against the Ankit Bawne-led side. Along with Shaw, promising youngster Arshin Kulkarni, No. 3 batter Siddhesh Veer, and captain Ankit Bawne himself were sent back to the dugout early, leaving Maharashtra reeling in the morning session. Following the top-order collapse, Raturaj Gaikwad steadied the innings with support from veteran Jalaj Saxena.

Shaw's dismal performance came just days after a belligerent knock of 181 off 219 deliveries in a practice game. In that match, Shaw had launched a brutal assault on his



former team Mumbai, showcasing the kind of form that once made him one of India's most promising young talents.

However, Shaw's sensational innings wasn't the biggest talking point of that warm-up match. He was involved in an ugly spat with his former teammate Musheer Khan following his dismissal. Attempting a slog-sweep, Shaw mistimed his shot and was

caught at deep fine leg. As he began walking back to the pavilion, tempers flared between him and Musheer, leading to a heated verbal exchange. The confrontation escalated when Shaw, visibly frustrated, appeared to fling his bat in the direction of his former teammates, prompting the umpire to step in and quickly defuse the situation. The incident caught the attention of both fans and officials, particularly in light of Shaw's turbulent exit from the Mumbai team. The 25-year-old opener had ended his long-standing association with the side earlier this year, opting to represent Maharashtra in search of a fresh start after a series of disciplinary issues and form slumps had stalled his once-promising career. Shaw's stock in Indian cricket has significantly declined since his debut in 2018. Despite a bright start, the batter has struggled to maintain consistency and has often found himself embroiled in controversies, both on and off the field. As a result, he has yet to fulfil the immense potential he showed early in his international career.

## Australia heading into Ashes with their worst team since 2010: Stuart Broad

New Delhi. (Agency)

England bowling great Stuart Broad has claimed that Australia are heading into the Ashes with their 'worst' team since 2010, as the war of words heats up ahead of the iconic series. Broad made the comment in response to former Australia opener David Warner's prediction that England would lose the series 4-0 down under. England's last win in Australia came in 2010-11, when Broad was part of a squad that won 3-1 to retain the urn. However, in their three subsequent tours, England suffered heavy defeats of 5-0, 4-0, and 4-0. "It's very, very difficult to win in Australia as an England side, or any side - it just is," Broad told the For the Love of Cricket podcast on BBC Sounds. "Australia have to be massive favourites. The question really was 'Which team's under the most pressure?' Well, Australia are under the most pressure because they're expected to win. They're brilliant at home. But they've got question marks over their team and question marks over [the fitness of] captain [Pat Cummins]."

Broad retired from playing after the Ashes series in England in 2023, when Australia retained the urn with a 2-2 draw. He added: "You wouldn't be outlandish in thinking - it's actually not an opinion, it's a fact - it's probably the worst Australian team since 2010 when England last won, and it's the best English team since



2010. "So those things match up to the fact it's going to be a brilliant Ashes series."

The first Test starts in Perth on 21 November, and Australia's preparations have been hit by the potential absence of skipper Cummins, who has not played since July due to lumbar bone stress in his back. The pace bowler is still recovering and has said he is "less likely than likely" to play in the opener. His absence would leave Australia with a bowling attack of Mitchell Starc, Josh Hazlewood, and Scott Boland, all in their mid-30s, while their other seamers are inexperienced or untried at Test level.

## Puerto Rico vs Argentina: Messi becomes player with most assists in international football

New Delhi. (Agency)

Argentina captain Lionel Messi reached another historic milestone on Tuesday, becoming the player with the most assists in men's international football. In a commanding 6-0 victory over Puerto Rico, Messi provided two assists, taking his international tally to 60 and surpassing Neymar and Landon Donovan, who each have 58. With this achievement, Messi is now just three assists shy of 400 across his professional career. Argentina wrapped up their US tour in style at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida—Messi's home ground with Inter Miami. While the captain did not score, he provided assists for Alexis Mac Allister and Lautaro Martinez, both of whom scored braces, with Gonzalo Montiel and an own goal from Steven Echevarria rounding off the 6-0 victory.

While widely regarded as one of the greatest goalscorers in football history, Messi's vision and creativity as a playmaker are equally remarkable. His first international

assist came more than 19 years ago during his World Cup debut in 2006, when Argentina defeated Serbia and Montenegro 6-0. In the first half against Puerto Rico, Messi showcased his trademark brilliance,



threading a precise pass to Gonzalo Montiel in the box to open the scoring. Later, he produced a clever back pass that led to Lautaro Martinez's second goal. These moments exemplify the precision, vision, and tactical intelligence that have made Messi a unique talent in world football. By

surpassing Donovan and Neymar, Messi has cemented his place not only as one of the most prolific scorers but also as one of the most gifted creators in international football history.

With the 2026 World Cup on the horizon, expectations for Messi remain sky-high. Having lifted the trophy in Qatar in 2022, he is widely expected to aim for another crowning achievement before concluding his international career. Overall, Messi now has 397 assists across 1,129 matches. He will return to Inter Miami as they prepare to face Nashville SC in Major League Soccer this Saturday. Argentina, ranked third in the world by FIFA, faced Puerto Rico, ranked 155th, which included some college players in their squad. Despite a near-miss from Leandro Antonetti early on, Argentina dominated throughout. Goalkeeper Emiliano Martinez made a crucial save, denying a shot that almost beat him from distance.

## Might be the last chance for Australian public to see Rohit-Kohli: Pat Cummins

**Australia captain Pat Cummins has called the upcoming ODI series against India a special occasion, suggesting it might be the last opportunity for fans in Australia to witness Virat Kohli and Rohit Sharma in action.**

New Delhi. (Agency)

Australia captain Pat Cummins has described the upcoming ODI series against India, starting Sunday in Perth, as special, noting it could be the "last chance" for fans Down Under to witness superstars Virat Kohli and Rohit Sharma in action in this country. The 32-year-old Cummins, sidelined due to a back injury, will be watching from the stands. Rohit and Kohli have been named in India's squad for the three-match ODI series

against Australia, starting in Perth on October 19. "Virat and Rohit have been part of almost every Indian side for the last 15 years, so this might be the last chance for the Australian public to see them playing out here," Cummins told JioHotstar. They've obviously been champions of the game for India and are always very well supported. Whenever we play them, the crowd gets loud," he added. The premier pacer admitted his disappointment at missing the series, which will also feature games in Adelaide and Sydney, followed by a five-match T20 International series from October 29.

"It's a shame to miss the white-ball series against India. I think the crowds are going to



be huge. There's already a lot of excitement built up here in Australia," he said. "So, whenever you miss a game, it's disappointing. But missing a big series like this is always a bit harder to take," he added. Cummins also offered his perspective on the approach Australia should follow

under stand-in captain Mitchell Marsh.

"It's three matches you want to win, but it's also about giving exposure to the younger guys coming through, particularly those who weren't part of the last World Cup. The goal is to try and play them, see what they can do, and make sure that once we get close to the World Cup, we know what our 15-man squad is going to be and that we're well placed," he said. On pacer Mitchell Starc's retirement from T20 international cricket to focus on his Test career, Cummins said he understands the thought process behind the decision.

"I knew it was on Starkey's mind for a little while, retiring from T20Is. Playing all three formats is tough. He's a couple of years older than me and has played 100 Test matches as well, quite a few more than I have," he said. "He wants to prioritise Test cricket. He's had a fantastic T20I career, and there are plenty of other guys who, while they may not do exactly what Starkey did, can step in and fill his shoes," he added.

# Kajol Mukherjee

## Recalls Growing Up Watching Mom Work '24/7,' Says She Didn't 'Want To Join Films'

Kajol's mother, Tanuja Mukherjee, is remembered for her iconic roles in films like Jewel Thief (1967) and Haathi Mere Saathi (1971), but behind the glamorous life everyone saw, there was constant hard work and struggle—growing up, this affected Kajol, who decided not to step into the world of movies. While speaking with The Hollywood Reporter India, Kajol talked about the struggles of her mom and how it shaped her opinion about the industry. Kajol, while talking about her mom's struggle, shared, "When I was growing up, I realised that she struggled a lot."

She further elaborated and revealed, "She worked 24/7 and didn't get paid even half as much as she should have. It wasn't a stable or continuous source of income. I remember thinking, 'I never want to work that hard.' She would work from seven in the morning till late at night, sometimes coming home only to bathe and head back to set. She did that for years when we were kids. Nobody could pay me enough to do that. That was the main factor that made me not want to be in films. Otherwise, with my mom, my dad, my grandfather... it was such a normal part of my life, so I was never starstruck by it."



Nobody could pay me enough to do that. That was the main factor that made me not want to be in films. Otherwise, with my mom, my dad, my grandfather... it was such a normal part of my life, so I was never starstruck by it."

### Kajol on keeping boundaries

Kajol also spoke about keeping certain boundaries and shared

that if she likes some scripts, there aren't many demands. She added, "I have a few clear boundaries. I will not subject myself to scenes of molestation or rape. I don't enjoy them as subjects, and I don't feel they're necessary to prove my worth as an actor."

### Kajol on actors working harder statement

During the conversation, Kajol was asked about her statement on Two Much, regarding actors working harder than employees who work 9-5. Explaining her comment, the actress said, "I was at an event in Jaipur. The flight to Jaipur was at 7 a.m., by the way. So I reached there, and the event was at about 3 p.m. And I was sitting at this event and somebody asked me, 'You have such a glamorous life.' I said, 'you're only looking at it from the point of view that, oh, she is so well dressed, and she's got makeup and she's sitting here in front of me. But you don't know that I took the 7 a.m. flight in the morning, for which I had to wake up at 5 in the morning and reach the airport by 6. So that I could board the 7 a.m. flight. And I have come here, got dressed, gotten ready, had lunch, and then gone immediately to do photos, one interview, and then come to sit over here in this chair in front of you. So I have had a packed day from 5 in the morning.'"



## 'Yahaan Sab Kuch Real Hota Hai': Badshah Slams People Calling Indian Idol Scripted



India's most iconic singing reality show, Indian Idol, returns for a new season on Sony Entertainment Television, bringing a wave of nostalgia and melody under the heartfelt theme — Yaadon Ki Playlist: Jahaan Awazein Aaj Wali Aur Gaane Aap Wale. Every time a reality show airs, a section of society often tends to tag it as scripted, and that often happens with Indian Idol too. Serving as a judge on the show, Badshah has now decided to shut this gossip once and for all.

### What is Badshah's take on Indian Idol being scripted?

Recently, judge Vishal shared a memorable story about Tabish, the brother of singer Danish, who is known for his incredible voice and also participated in Indian Idol. He said, "Last time, while leaving, he hummed something so incredible that we asked him to sing it, and it blew us away. People even questioned and trolled us if it was planned or scripted because it was so impressive."

Responding to this, Badshah made it clear, "I just want to tell the camera that yahaan kuch scripted nahi hota. Sab kuch real hota hai. Scripted hota toh main toh follow hi nahi kar pata script."

Badshah Moved By Contestant's Emotional Journey In a recent promo shared on the Sony Channel's Instagram, the rapper was extremely moved by contestant Dharmesh's emotional journey.

Dharmesh, who hails from Chandigarh, comes from a musical family but has an unhealed wound — he hasn't seen his daughter since 2019, a few months after she was born. The separation pushed him into depression, but music gave him hope and a sense of purpose. Speaking to the contestant, the DJ Wale Babu singer said, "Don't let me down. Don't let a man down. Don't let a father down. Dharmesh, apne emotion ko itna haawi mat hone do. Mujhe pata hai yeh emotion kya hai, main bhi apni bacchi se door rehta hoon."

### About Indian Idol

Promising to blend today's talent with songs of yesteryears, this season is set to be a musical celebration of Indian music, filled with emotions, memories, and extraordinary talent.

## Aneet Padda Gets A Sweet Birthday Wish From Saiyaara Director Mohit Suri: 'Love You Forever And Ever'



Aneet Padda turned 23 on Monday, October 13, and celebrated it with her loved ones. The actress rose to overnight fame after featuring in Mohit Suri's romance drama Saiyaara. The film, also starring Ahaan Panday as the lead, broke several box office records, becoming a blockbuster success. It is no secret that Aneet shares a warm bond with the director, which is evident from her social media posts. So, it was not a surprise that Mohit Suri came up with the sweetest wish for the birthday girl.

On Tuesday, Mohit Suri uploaded a picture with Aneet Padda on Instagram. In the snap, Aneet Padda flashed a soft smile while taking the selfie. The director, on the other hand, planted an affectionate kiss on her head. His lovely side note read, "Happy birthday, my star Aneet Padda! Thank you for lighting the way for all of us. Love you forever and ever and ever."

It's all good," while another netizen commented, "Such a strong message one of the best posts on the gram in recent times! More power to you."

### Aneet Padda Celebrates Birthday With Ahaan Panday At Coldplay Concert

Aneet Padda, who is rumoured to be dating her Saiyaara co-star Ahaan Panday, celebrated her birthday night enjoying a Colplay concert. Ahaan dropped a set of pictures and a video from the musical night on his now-disappeared Instagram Stories. The first photo was a playful selfie where the duo smiled ear-to-ear, grooving to the music. The next image was a candid shot of Aneet, staring at the sky illuminated with fireworks. In the last slide, the two displayed their LED bracelets.

### Ahaan Panday Feeds Birthday Cake To Aneet Padda

In another video, going viral on Reddit, Aneet Padda was seen cutting a birthday cake with Ahaan Panday by her side. The actor took a spoonful and fed it to the actress before the two exchanged smiles and laughter. Adding to the magic was the music of Saiyaara's soulful title track playing in the background.



## Rashmika Mandanna's Picture-perfect Moment With Thamma Co-Star Ayushmann Khurrana Is The Cutest

Rashmika Mandanna and Ayushmann Khurrana are the new talk of the town for their on-screen chemistry. They have been in the headlines for their upcoming film 'Thamma'. Now, the actress has shared a cute picture with Ayushmann on her Instagram story, captioning it as "Delhi here we come" #Thamma. In the picture-perfect moment, both were seen in traditional attire and smiling at the camera. Rashmika was seen wearing a pink kurta, and Ayushmann was seen in a white kurta with sunglasses and a big smile. Rashmika and Ayushmann will be seen in the upcoming horror comedy Thama. The duo visited Delhi for the promotion of their upcoming movie. It will be interesting for fans to see their chemistry in the upcoming movie.

### About Thama

Thama is a Romantic Comedy horror movie directed by Aditya Sarpotdar. The film is the 5th instalment in the Maddock Horror comedy universe. Along with Rashmika and Ayushmann, the film also features Nawazuddin Siddiqui and Paresh Rawal. The movie basically revolves around World of Vampires and is billed as a "Bloody love story." The movie is in the last stage of its promotions and is ready to hit theatres on Diwali this year, i.e., 21 October. It will be the first release of Ayushmann on Diwali, and the actor seems very excited about that.

### Thama Trailer Launch

The Thama official teaser was launched on August 19, 2025. The teaser starts by portraying Ayushman and Rashmika as lovers and showing that they are destined to be together, showing a perfect love story. But the arrival of Nawazuddin Siddiqui changes the plot of the

story, adding thrill and suspense to keep the viewers fully focused on the story.

Ayushmann Khurrana portrays Alok, who is termed "Insaaniyat ki aakhri umeed", the last hope of humanity. Despite the makers concealing most of his character details, Alok is anticipated to signify empathy in a world filled with upheaval. Rashmika will be seen playing Tadaka, who is said to be "Roshni ki ek hi pehli kiran", the very first ray of light. The character



of her is a source of light in the middle of a love and chaos-torn world. Rashmika Mandanna talked about her experience during the shooting of Thama, which was one of her most challenging projects. In an interview with The Nog Magazine, she mentioned, "Oh my God! Thama! We really had to hustle hard for this film."

I was convinced that I had seen all kinds of shoots after doing 24-25 films. But Thama made me realise that I was not prepared for it. I am convinced that this film will change people's perception of me."

